RNI No.DELHIN/2011/41355

दिल्ली से प्रकाशित

अप्रैल 2026 वर्ष 15 अंक 173 मूल्य₹20

प्राइम स्पेक्टेटर

राजनीति पीएसयू और अपराध पर केंद्रित पत्रिका

महायुद्ध क्या होगा?

'खेला होबे' या बिगड़े ?

PRIME INDIA MEDIA HOUSE

PRIME CRIME INDIA

www.primecrimeindia.com

PSU TODAY

NETA INDIA

www.netaindia.com

एनटीपीसी NTPC तालचेर कनिहा
TALCHER KANIHA

ODISHA'S LARGEST POWER STATION

With an installed capacity of **3010 MW** and making significant contributions to the lives of communities surrounding the station.

TALCHER SUPER THERMAL POWER STATION
Kaniha, PO: Deepshikha, Dist : Angul, Odisha - 759147

/ntpc1 /ntpcltd1 /ntpclimited /company/ntpc /ntpclimited

Leading the Power Sector

संपादकीय

नासिर खान
संपादक

अमेरिकी पायलट की मां और ईरानी माताओं का दर्द!

सोशल मीडिया पर एक मां की प्रार्थना से युद्ध की मानवीय पीड़ा उजागर हुई। अमेरिकी फाइटर पायलट के सकुशल वापसी के बाद से उस अमेरिकी मां के चेहरे पर मुस्कान है। लेकिन ईरान में अमेरिकी–इजरायली हमले में मारे गए 1600 से अधिक नागरिकों की माताओं का दर्द को भी समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक मां का संदेश आया। वह अपने फाइटर पायलट बेटे के लिए परेशान थीं। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा आज की रात प्रार्थनाओं में उन दो एफ–15 पायलटों को याद रखें, जिनके विमान ईरान में गिरा दिए गए हैं। मां साझा होती हैं और उनकी प्रार्थनाएं सभी पर असर करती हैं। अमेरिका ने ईरान में तलाशी अभियान चलाकर अपने पायलट बचा लिए, उस मां के बेटे को भी। लेकिन यह युद्ध का सिर्फ एक पहलू है, दूसरी तरफ ईरान की सैकड़ों मां आंसुओं में डूबी हैं। इस युद्ध में अब तक साढ़े तीन हजार से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। 1600 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और करीब 250 बच्चे। संघर्ष के पहले ही दिन तेहरान के पास मिनाब में एक स्कूल पर अमेरिकी मिसाइल गिरी, जिसमें सौ से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। ईरान की जिन मां ने अपने बच्चों को गंवाया है, क्या उनके दुख की कल्पना भी की जा सकती है! फिर पश्चिम एशिया के उन लोगों की भी सोचिए, जो बमों–मिसाइलों के धमाकों की दहशत में दिन–रात गुजार रहे हैं। कहीं यह युद्ध उन्हें हमेशा के लिए बदल न दे, अमेरिका और इस्राइल इस युद्ध को जरूरी बता रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। यह सौर सार्वविदित है कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलता। हिंसा हमेशा प्रतिहिंसा को जन्म देती है, जिसमें मानवता की आहूति दी जाती है। युद्ध से फायदा होता है तो सिर्फ हथियार बेचने वाली कंपनियों को और उन सत्ताधीशों को, जो इसकी आड़ में राष्ट्रवाद का ज्वार बढ़ाकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंसा का हमेशा इसलिए विरोध करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक, अगर इससे कुछ अच्छा दिखता भी है, तो वह अस्थायी होता है, लेकिन उसका बुरा असर स्थायी। युद्ध इसलिए भी कभी जरूरी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे छूट जाते हैं दुख, प्रतिशोध, अशांति और तबाही। इनसे उबरने में बरसों लग जाते हैं। अगर रूस–यूक्रेन युद्ध की बात करें तो उसमें जितना नुकसान यूक्रेन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, उसे दोबारा खड़ा करने में करीब 600 अरब डॉलर लगेंगे। एक करोड़ यूक्रेन वासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, 60 लाख तो देश ही छोड़कर चले गए। इस युद्ध ने भी कई माताओं की गोद सूनी कर दी है। पश्चिम एशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है। शांति से समृद्धि का द्वार खुलता है और युद्ध से विनाश का।

‘नक्सलवाद लगभग खत्म’
अपने अंत की ओर है भारत का सबसे लंबा आंतरिक संघर्ष?

—:पेज 33 :—

प्राइम स्पेक्टेटर

संपूर्ण हिंदी मासिक पत्रिका

RNI No.DELHIIN/2011/41355

DAVP No.0813F27125-025

वर्ष-15,अंक:173, अप्रैल 2026

मल्य ₹ 20

संपादक
नासिर खान

सलाहकार संपादक
राकेश त्रिपाठी
डॉ. ईशा
अर्चना ज्योती

राजनीतिक संपादक
इंजी.ए पी सिंह

संपादक (सूचना प्रौद्योगिकी)
प्रशांत दत्त मिश्रा

कानूनी सलाहकार
डी.बी.गोस्वामी,सलीम खान
(एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)

चीफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव
समीर अख्तर

विदेश प्रतिनिधि
विकास पारिक (लंदन)

प्रमुख प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो प्रमुख
सतपाल सिंह तंवर

लखनऊ ब्यूरो प्रमुख
अशोक तिवारी

मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख
श्वेतांक वर्मा

हरियाणा ब्यूरो प्रमुख
संजय सिन्हा

उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख
सुनील नेगी

पूर्वांचल ब्यूरो प्रमुख
शाहिद अस्करी

दक्षिणांचल ब्यूरो प्रमुख
इमरान खान

बरेली मण्डल ब्यूरो प्रमुख
योगेंद्रपाल सिंह कौशल

बिहार ब्यूरो प्रमुख
शक्ति प्रकाश

महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख
राजकुमार केशरवानी

हिमाचल ब्यूरो प्रमुख
साहिल शर्मा

राजस्थान ब्यूरो प्रमुख
रानू पाठक

पश्चिम बंगाल,दिल्ली एनसीआर ब्यूरो प्रभारी
नरेश कुमार श्रीवास्तव

विशेष संवाददाता
गुफरान खान

प्रमुख संवाददाता
गुलशन अरोड़ा

संघर्ष से आईपीएल तक पहुंचे अनिकेत वर्मा...49

ईरान से भारत लौटे जहाजियों की आपबीती...19

संपादकीय 3

अमेरिका-ईरान युद्ध 50 अरब डॉलर का संकट.............................15

पीएसयू की खबरें.................. 22

सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द......27

छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता कानून......38

हिंदू परिवार के पाँच भाइयों ने ईदगाह के लिए दान कर दी जमीन............40

बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है विज्ञान 48

उत्तराखंड के दिव्यांग कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया............50

क्षेत्रीय प्रतिनिधि

दिल्ली ब्यूरो
मोहम्मद आसिफ (वरिष्ठ संवाददाता)

मथुरा ब्यूरो
विनय चौधरी (संवाददाता)

कानपुर ब्यूरो
अजय कुमार द्विवेदी (वरिष्ठ संवाददाता)

बलिया ब्यूरो
डॉ.कलीम वारसी (वरिष्ठ संवाददाता),

आरा ब्यूरो
विमलेश कुमार (संवाददाता)

हाजीपुर ब्यूरो
राहुल कुमार (संवाददाता)

कार्यालय

कॉरपोरेट ऑफिस

91, फर्स्ट फ्लोर जे एंड के ब्लॉक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली– 110092

संपादकीय कार्यालय

आर–141/3 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली–110092
मोबाइल–9718647540Ph.011-46536014
ईमेल–primespectator@gmail.com,primeindia-mediahouse@gmail.com
वेबसाइट–primeindiamediahouse.com
primecrimeindia.com & netaindia.com

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नासिर खान द्वारा ANEJA PRINTERS,C–11,SECTOR-10,NOIDA (UP)से मुद्रित तथा आर–141/3 रमेश पार्क,लक्ष्मी नगर,दिल्ली–110092 से प्रकाशित। सभी पदाधिकारी अवैतनिक हैं। प्राइम स्पेक्टेटर के किसी भी रचना के प्रकाशन से पहले संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित लेख,लेखक के निजी विचार हैं। सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

बंगाल में सत्ता का संग्राम : क्या चौथी बार भी जीतेंगी ममता दीदी, या बदलेगा खेला?

नासिर खान
वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम बंगाल की राजनीति में साल 2011 सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं था वह एक युगांतकारी परिवर्तन था। 34 वर्षों तक सत्ता पर काबिज वाम मोर्चे को हटाकर ममता बनर्जी ने न सिर्फ सरकार बदली, बल्कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का चेहरा भी बदल दिया। उस समय बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को यह भरोसा नहीं था कि एक सड़क से संघर्ष करके निकली नेता इतने जटिल राज्य का प्रशासन स्थिरता से चला पाएंगी। लेकिन समय ने धीर –धीरे इन आशंकाओं को पीछे छोड़ दिया। ममता बनर्जी लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बनीं और आज भी राज्य की राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बनी हुई हैं। अब जब 2026 का विधानसभा चुनाव सामने है, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है क्या

अन्य राज्यो में मतदान एवं परिणाम तारीखों की घोषणा

देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीखें तय कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा, पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।

तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।

असम, केरल और पुडुचेरी में भी एक-एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इन सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

वह चौथी बार जीतकर इतिहास रचेंगी, या इस बार बंगाल की राजनीति एक नया मोड़ लेने जा रही है? यह चुनाव सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं है। यह ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत, उनकी विश्वसनीयता और बंगाल की दिशा तय करने वाला चुनाव भी माना जा रहा है।

2011 की क्रांति से 2026 की चुनौती तक

2011 का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बदलाव की राजनीति का प्रतीक था। जनता बदलाव चाहती थी और तृणमूल कांग्रेस उस बदलाव की आवाज बन गई थी। लेकिन 2026 का चुनाव बिल्कुल अलग परिस्थिति में हो रहा है। अब ममता बनर्जी सत्ता विरोधी लहर, प्रशासनिक सवालों, भ्रष्टाचार के आरोपों और सबसे बढ़कर Bharatiya Janata Party की मजबूत चुनौती का सामना कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव साबित हो सकता है।

एंटी-इनकम्बेंसी : लगातार चौथी जीत की सबसे बड़ी बाधा

लगातार तीन कार्यकाल तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी सरकार के सामने एंटी–इनकम्बेंसी स्वाभाविक चुनौती बन जाती है। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है। कानून–व्यवस्था, रोजगार के अवसर, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे विपक्ष के लिए बड़े चुनावी हथियार बन चुके हैं। खासकर युवा मतदाता रोजगार और विकास के मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी को इस बार सिर्फ विपक्ष से नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं से भी मुकाबला करना पड़ रहा है।

वोटर लिस्ट विवाद चुनावी गणित बदलने वाला मुद्दा

इस बार चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बनकर उभरा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 63 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटाए गए हैं, जबकि लाखों नाम अभी भी जांच के दायरे में हैं। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब राज्य में मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 82 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो देश के सबसे अधिक मतदान प्रतिशतों में शामिल था। ऐसे में इस बार मतदान प्रतिशत किस दिशा में जाएगा, यह चुनावी परिणामों पर बड़ा असर डाल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कई बड़े घोटालों के आरोप लगे हैंकृजैसे शिक्षक भर्ती विवाद, पीडीएस घोटाला और कैटल स्मगलिंग केस। इन मामलों में कई मंत्रियों और अधिकारियों की गिरफ्तारी ने विपक्ष को

सरकार पर हमला करने का मौका दिया है। विशेषकर कोलकाता और आसपास के शहरी क्षेत्रों में इन मुद्दों का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। शहरी मतदाता आमतौर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर अधिक संवेदनशील होते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर शहरी इलाकों में असंतोष बढ़ता है, तो यह चुनावी समीकरण बदल सकता है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक मुद्दों की भूमिका पहले की तुलना में अधिक बढ़ी है। वक्फ संशोधन कानून और उससे जुड़े विवादों ने राज्य की राजनीति को और संवेदनशील बना दिया है। मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में विरोध प्रदर्शन और तनाव की घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि इस बार चुनाव में सांप्रदायिक मुद्दे भी मतदान के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मुद्दों का असर ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में अधिक दिखाई दे सकता है। चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषण ाएं की गईं। इनमें महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाना, बेरोजगार युवाओं के लिए 'बांग्लार युवा साथी' योजना शुरू करना और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान की घोषणा शामिल है।

इन घोषणाओं को राजनीतिक विश्लेषक चुनावी रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिला मतदाता ममता बनर्जी की सबसे मजबूत ताकत मानी जाती हैं। ऐसे में महिलाओं को लक्षित योजनाओं का चुनावी असर महत्वपूर्ण हो सकता है।

बीजेपी की चुनौती : 2026 का असली मुकाबला

पश्चिम बंगाल में Bharatiya Janata Party पिछले एक दशक में तेजी से मजबूत हुई है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसने राज्य की राजनीति को द्विध्रुवीय बना दिया। अब 2026 का चुनाव सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत करती है, तो मुकाबला और कड़ा हो सकता है।

फिर भी क्यों मजबूत दिखती हैं ममता बनर्जी?

सभी चुनौतियों के बावजूद ममता बनर्जी आज भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हैं। उनका व्यक्तिगत करिश्मा, जमीनी संपर्क और संगठन पर पकड़ उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि विपक्ष अभी तक ऐसा कोई सर्वस्वीकार्य चेहरा सामने नहीं ला पाया है, जो ममता बनर्जी को सीधे चुनौती दे सके। यही वजह है कि तमाम आरोपों और विरोध के बावजूद तृणमूल कांग्रेस अभी भी चुनावी दौड़ में मजबूत स्थिति में दिखाई देती है।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ सरकार बदलने या बचाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव तय करेगा कि राज्य की राजनीति अगले दशक में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक तरफ ममता बनर्जी का अनुभव और जनाधार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की बढ़ती चुनौती। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य का भी मुकाबला बन चुका है। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है क्या वे ममता बनर्जी को चौथी बार मौका देकर इतिहास रचेंगी, या राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा?

क्या बदली है चुनाव आयोग की रणनीति, और किस ओर झुक सकता है राजनीतिक संतुलन?

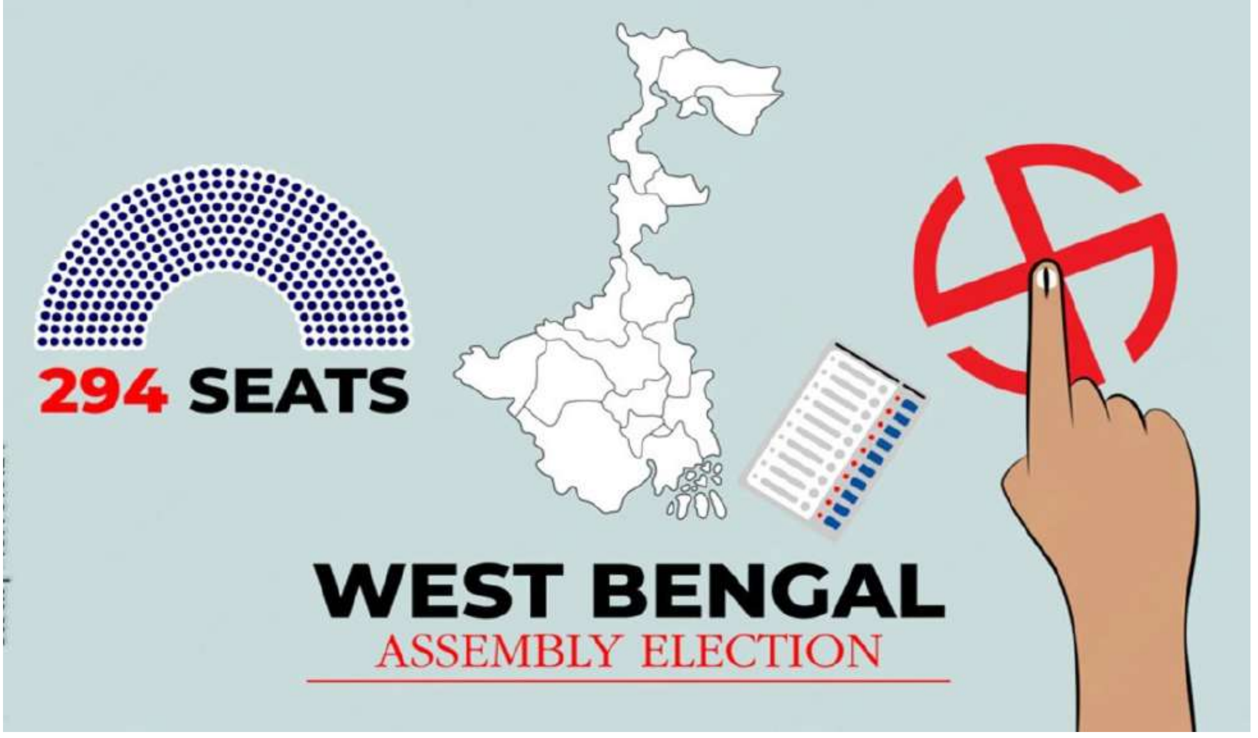

नरेश श्रीवास्तव
ब्यूरो प्रमुख पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे जीवंत, संघर्षपूर्ण और प्रतीकात्मक राजनीतिक धरातलों में से एक रही है। 2026 का विधानसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं है। जैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से पश्चिम बंगाल सहित असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, बंगाल की राजनीति में एक नया ताप महसूस होने लगा। पश्चिम बंगाल में इस बार मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होगा और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन इस चुनाव की असली कहानी सिर्फ तारीखों की घोषणा भर नहीं है। यह चुनाव कई सवालों, विवादों, रणनीतियों और ऐतिहासिक संभावनाओं से भरा हुआ है खासकर तब, जब चरणों की संख्या घटाकर सिर्फ दो कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है क्या बदला है इस बार? और क्यों यह चुनाव पिछले चुनावों से इतना अलग दिखाई दे रहा है?

दो चरणों में मतदान : क्या है इसके पीछे की रणनीति?

2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान हुआ था। वह चुनाव न केवल लंबा चला, बल्कि देश की राजनीतिक ऊर्जा का केंद्र भी बन गया था। उस समय सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा की आशंकाएं और प्रशासनिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणों की संख्या बढ़ाई गई थी। लेकिन 2026 में वही राज्य अब सिर्फ दो चरणों में मतदान कराने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, आयोग ने लंबी समीक्षा और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। आयोग का तर्क है कि कम चरणों में मतदान कराने से चुनावी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, कम तनावपूर्ण और प्रशासनिक दृष्टि से अधिक प्रभावी बन सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं– सुरक्षा बलों की बेहतर उपलब्धता, प्रशासनिक तैयारी में सुधार, तकनीकी निगरानी क्षमता में वृद्धि और चुनावी प्रक्रिया को छोटा और केंद्रित रखने की रणनीति । हालांकि विपक्षी दलों के कुछ नेता इस फैसले को लेकर आशंकाएं भी जता रहे हैं। उनका मानना है कि कम चरणों में मतदान से चुनावी माहौल अधिक तीखा और तेज हो सकता है।

मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी असली लड़ाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सबसे बड़ी और विवादित कहानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR बन गया है। आजादी के बाद यह

पहला अवसर है जब राज्य में पिछले चुनावों की तुलना में कुल मतदाताओं की संख्या कम हुई है। विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद लगभग 63 लाख 66 हजार मतदाताओं के नाम अंतिम सूची से हटाए गए हैं। इसके अलावा करीब 60.6 लाख नाम अभी भी जांच की प्रक्रिया में हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन सत्ताध ाारी दल और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर गंभीर मतभेद सामने आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें अभी भी समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम दोबारा जुड़वाने का अवसर दिया गया है। फिर भी यह सवाल बना हुआ हैकृक्या इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने से मतदान प्रतिशत प्रभावित होगा? 2021 के चुनावों में राज्य में 7 करोड़ 30 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत थे और 82.3 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो देश के सबसे अधिक मतदान प्रतिशतों में से एक था। क्या 2026 में भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिलेगा यह एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट की एंट्री : चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी

मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद ने मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 500 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को विवादित मतदाता प्रविष्टियों के निपटारे की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा 10 मार्च 2026 को अदालत ने विशेष अपीलीय ट्रिब्यूनलों के गठन का निर्देश भी दिया। इन ट्रिब्यूनलों की अध्यक्षता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं और उनका काम उन मतदाताओं की अपीलों पर सुनवाई करना है जिनके नाम सूची से हटाए गए थे। यह हस्तक्षेप इस बात का संकेत है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और भरोसे का मुद्दा इस बार बेहद महत्वपूर्ण बन गया है।

क्या ममता बनर्जी रचेंगी इतिहास?

पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक राजनीतिक युग का नाम बन चुकी हैं। 2011 में वाम मोर्चा के 34 वर्षों के लंबे शासन को समाप्त कर सत्ता में आईं ममता बनर्जी ने लगातार तीन बार चुनाव जीतकर राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। यदि 2026 में भी उनकी पार्टी जीत दर्ज करती है, तो वे पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन जाएंगी जिन्होंने लगातार चार बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया हो। यह उपलब्धि उन्हें देश की सबसे लंबे समय तक प्रभावी महिला मुख्यमंत्रियों की सूची में विशेष स्थान दिला सकती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है।

भाजपा की रणनीति चेहरा या सिर्फ

नेतृत्व का प्रभाव?

भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2021 के चुनावों में पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ा था और प्रचार का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा था। यह रणनीति पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दिल्ली जैसे राज्यों में भी अपनाई थी, जहां चुनाव जीतने के बाद नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा पश्चिम बंगाल में भी वही रणनीति दोहराएगी? या इस बार राज्य स्तर का कोई चेहरा सामने आएगा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना या न करनाकृदोनों ही रणनीतियां चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं।

वाम दल, कांग्रेस और आईएसएफ क्या बनेगा तीसरा मोर्चा प्रभावी?

पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वाम दलों के प्रभाव में रही है। हालांकि पिछले दो चुनावों में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा है, फिर भी वे अभी पूरी तरह राजनीतिक समीकरण से बाहर नहीं हुए हैं। 2021 के चुनावों में वाम दलों, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में आईएसएफ नेता नौशाद सिद्दीकी भांगर सीट जीतने में सफल रहे थे। लेकिन 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। इस बार वाम दल और आईएसएफ साथ हैं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, यह बदलाव चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है।

भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर का तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाना भी इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। उन्होंने 'जनता उन्नयन पार्टी' नाम से नया राजनीतिक दल बनाया है और संकेत दिया है कि वे इसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर मैदान में उतरेंगे। हालांकि नई पार्टी का प्रभाव कितना व्यापक होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसका असर जरूर पड़ सकता है।

भ्रष्टाचार के आरोप चुनावी बहस का स्थायी मुद्दा

इस चुनाव में शासन और प्रशासन से जुड़े मुद्दे फिर से केंद्र में आ गए हैं।

भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। इनमें विशेष रूप से शिक्षक भर्ती घोटाला कथित कोयला तस्करी मामला जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताती रही है। लेकिन यह भी सच है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद ने इन मुद्दों को कुछ हद तक पीछे ध ाकेल दिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर राज्य की राजनीति में तनाव साफ दिखाई दिया। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पांच दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना भी की। यह टकराव सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास का भी सवाल बन गया है।

चुनाव आयोग की जमीनी तैयारी

चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने राज्य का दौरा किया था। इस दौरान सुरक्षा स्थिति, प्रशासनिक तैयारी, राजनीतिक वातावरण का विस्तृत आकलन किया गया। इसी समीक्षा के बाद दो चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया गया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है। यह चुनाव कई बड़े प्रश्नों का जवाब देगा क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में लौटेंगी? क्या भाजपा अपनी राजनीतिक मौजूदगी को जीत में बदल पाएगी? क्या वाम दल फिर से राजनीतिक जमीन हासिल कर पाएंगे? क्या मतदाता सूची विवाद मतदान प्रतिशत को प्रभावित करेगा?

इन सभी सवालों के जवाब 4 मई को सामने आएंगे।

लेकिन उससे पहले यह तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धरती आने वाले दिनों में देश की सबसे गर्म चुनावी प्रयोगशाला बनी रहने वाली है। और शायद यही बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान भी है यह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती, इतिहास लिखती है।

चौरंगी विधानसभा सीट : क्या इस बार संतोष पाठक छीन लेंगे तृणमूल की परंपरागत सीट?

नरेश कुमार श्रीवास्तव
पश्चिम बंगाल ब्यूरो प्रमुख

पश्चिम बंगाल की सबसे प्रतिष्ठित और हाई प्रोफाइल शहरी विधानसभा सीटों में शामिल चौरंगी में इस बार का चुनाव बेहद रोचक होता जा रहा है। लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के कब्जे वाली इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संतोष पाठक ने मुकाबले को असाधारण रूप से दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनाव केवल पार्टी बनाम पार्टी नहीं बल्कि चेहरे बनाम चेहरा हो गया है, जहां व्यक्तिगत जनाधार परिणाम को प्रभावित कर सकता है।

काफी समृद्ध है राजनीतिक इतिहास

कोलकाता के व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र माने जाने वाले चौरंगी विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास काफी समृद्ध रहा है। 1957 में अस्तित्व में आई इस सीट पर शुरूआती दशकों में कांग्रेस का दबदबा रहा और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बना ली। 2001 से लेकर अब तक तृणमूल लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती रही है, जिससे यह सीट पार्टी का सुरक्षित गढ़ मानी जाती रही है। वर्तमान विधायक नैना बंदोपाध्याय, जो वरिष्ठ तृणमूल नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी हैं, इस सीट पर लगातार जीत हासिल करती रही हैं। 2014 के उपचुनाव में जीत से शुरू हुआ उनका सफर 2016 और 2021 में भी जारी रहा। 2021 में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को 45 हजार 344 वोटों के बड़े अंतर से हराकर अपनी मजबूत स्थिति साबित की थी। उनके पक्ष में तृणमूल का मजबूत संगठन, अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन और स्थानीय नेटवर्क को बड़ी ताकत माना जाता है। हालांकि इस बार मुकाबला पहले जैसा आसान नहीं दिख रहा। भाजपा ने संतोष पाठक को उम्मीदवार बनाकर चुनाव को नई दिशा दे दी है। संतोष पाठक का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था और लंबे समय तक इलाके में सक्रिय रहने के कारण उनकी व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक स्वीकार्यता मजबूत मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें केवल भाजपा कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि अन्य दलों के समर्थकों का भी एक वर्ग पसंद करता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संतोष पाठक की सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यक्तिगत छवि और जमीनी संपर्क है। हिंदी भाषी मतदाताओं, व्यापारियों और पारंपरिक कांग्रेस समर्थकों के बीच उनकी पकड़ भाजपा के लिए इस सीट पर नया समीकरण बना सकती है। खासतौर पर यह भी माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस और वामपंथी दलों का पारंपरिक वोट पूरी तरह उनके साथ नहीं जाता और उसका एक हिस्सा भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है तो मुकाबला तृणमूल के लिए कठिन हो सकता है।

मुस्लिम मतदाता हैं निर्णायक

चौरंगी सीट का सामाजिक समीकरण भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यहां लगभग 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक मतदाता हैं, जो अब तक तृणमूल के साथ मजबूती से जुड़े रहे हैं। यदि यह समर्थन इस बार भी कायम रहता है तो नैना बंदोपाध्याय को फायदा मिल सकता है। लेकिन भाजपा जिस तरह शहरी मतदाताओं, मध्यवर्ग और बंगाली वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है, उससे चुनाव का गणित बदल भी सकता है। पिछले कुछ चुनावी आंकड़े भी संकेत देते हैं कि भाजपा इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी जमीन मजबूत कर रही है। 2019 के बाद से पार्टी मुख्य चुनौती देने वाली ताकत बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरने के बाद हाल के चुनावों में थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन वह अभी भी निर्णायक स्थिति में नहीं दिखती। ऐसे में कांग्रेस–वाम गठबंधन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उनके वोट किस दिशा में जाते हैं, यह परिणाम को प्रभावित कर सकता है। चौरंगी पूरी तरह शहरी सीट है जहां मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है और आमतौर पर संगठित वोट और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि ज्यादा असर डालती है। यही वजह है कि इस बार भी पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार की स्वीकार्यता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि यदि संतोष पाठक विपक्षी मतों को एकजुट करने में सफल रहते हैं और अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को वोट में बदल पाते हैं तो यह सीट तृणमूल के हाथ से निकल भी सकती है। वहीं तृणमूल अपनी संगठनात्मक ताकत और पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे इस सीट को बचाए रखने की पूरी कोशिश में है। कुल मिलाकर चौरंगी में इस बार मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। एक तरफ तृणमूल के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ भाजपा इस सीट को कोलकाता की राजनीति में बड़ी प्रतीकात्मक जीत में बदलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या संतोष पाठक तृणमूल के मजबूत किले में सेंध लगा पाएंगे या नैना बंदोपाध्याय एक बार फिर अपनी जीत की परंपरा को कायम रखेंगी।

क्या खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा के लिए नई रणनीति की जरूरत है?

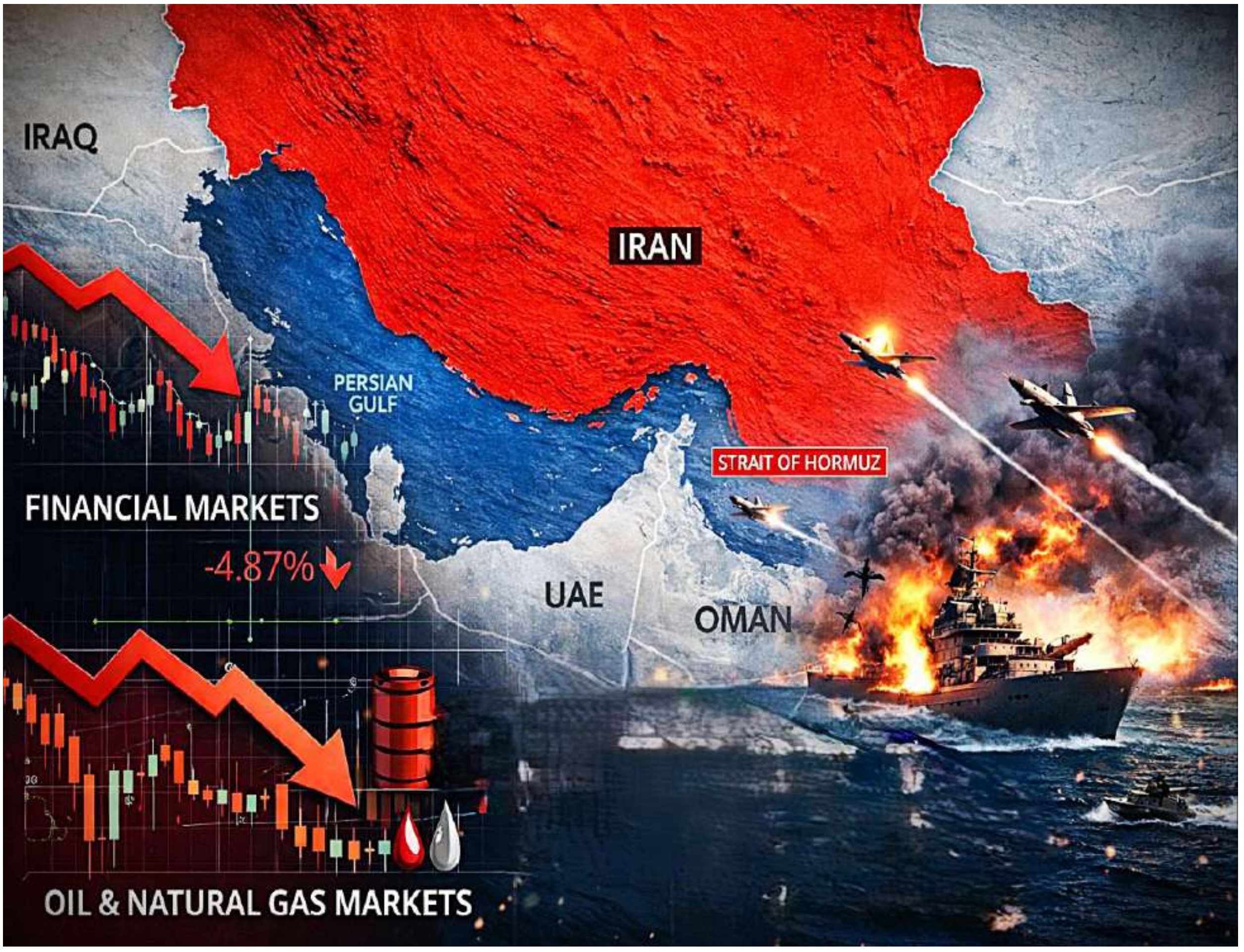

मध्य–पूर्व में हाल ही में हुए संघर्ष ने खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। वर्षों से दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों खासतौर पर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के साथ किए गए रक्षा समझौतों के बावजूद यह सवाल अब पहले से ज्यादा तेजी से उठ रहा है कि क्या मौजूदा सुरक्षा ढांचा भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? इस संघर्ष ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि केवल बाहरी सुरक्षा साझेदारियों पर निर्भर रहना दीर्घकालिक रणनीति नहीं हो सकती। परिणामस्वरूप खाड़ी देशों के सामने अब अपनी सामूहिक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल–अंसारी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ओर संकेत किया कि बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए खाड़ी देशों को अपनी साझा सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा रक्षा साझेदारियां युद्ध के दौरान रक्षात्मक दृष्टि से प्रभावी साबित हुई हैं। उनके अनुसार, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए खाड़ी देशों के बीच बेहतर क्षेत्रीय समन्वय आवश्यक है। यह स्थिति एक बड़े सवाल को जन्म देती है क्या वैश्विक शक्तियों पर निर्भरता खाड़ी देशों के लिए लंबे समय तक प्रभावी सुरक्षा विकल्प बनी रहेगी, या अब क्षेत्रीय सहयोग और नई रक्षा साझेदारियां भविष्य की दिशा तय करेंगी?

संघर्ष में खाड़ी देशों की भूमिका पर उठते सवाल

रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और अमेरिकी पत्रकार सेबेस्टियन रुब्लिन का मानना है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर खाड़ी देशों में स्थित अपने सैन्य ठिकानों से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप ईरान ने जवाबी प्रतिक्रिया दी। उनके अनुसार, इस संघर्ष में खाड़ी देशों को पूरी तरह निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने "चुपचाप" अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए

प्रोत्साहित किया और इसे ईरान को कमजोर करने के अवसर के रूप में देखा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कतर और बहरीन जैसे छोटे खाड़ी देश इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। वाशिंगटन स्थित गल्फ इंटरनेशनल फोरम की कार्यकारी निदेशक दानिया जफर का मानना है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों का खाड़ी देशों की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनके अनुसार, अमेरिकी मौजूदगी लंबे समय तक एक निरोधाक शक्ति (deterrence) के रूप में काम करती रही, जिसके कारण ईरान ने सीधे खाड़ी देशों पर हमला करने से परहेज किया।

क्या समस्या रक्षा समझौतों में है या रणनीतिक निर्णयों में?

कुवैत विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर हमाद अल–थुनिन का दृष्टिकोण इस बहस को एक अलग दिशा देता है। उनके अनुसार समस्या रक्षा समझौतों में नहीं, बल्कि रणनीतिक निर्णय–प्रक्रिया में है। उनका मानना है कि अमेरिका ने इस युद्ध में प्रवेश करते समय खाड़ी देशों के हितों को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी। इसके बावजूद, वे यह भी मानते हैं कि खाड़ी देशों ने ईरान के साथ अपने संबंधों में हमेशा कूटनीति को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है। संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठा कि खाड़ी देशों ने ईरानी हमलों का प्रत्यक्ष सैन्य जवाब क्यों नहीं दिया। दानिया जफर के अनुसार खाड़ी देशों ने अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों के माध्यम से प्रभावी बचाव किया। उदाहरण के तौर पर कतर ने कई मौकों पर लगभग सभी मिसाइलों को रोकने में सफलता प्राप्त की। हमाद अल–थुनिन के अनुसार खाड़ी देशों द्वारा प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से बचने के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं –

यह उनका युद्ध नहीं था उन्होंने इस संघर्ष की शुरुआत नहीं की और यह उनके दीर्घकालिक हित में नहीं था उनके अनुसार यह निर्णय कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक धैर्य का संकेत है।सेबेस्टियन रुब्लिन का मानना है कि इस संघर्ष ने ईरानी ड्रोन तकनीक से उत्पन्न खतरे को उजागर किया है। कम लागत वाले ड्रोन जिनकी कीमत लगभग 20 से 40 हजार डॉलर तक होती है के खिलाफ पैट्रियट या थाड जैसी महंगी प्रणालियों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण साबित होता है। युद्ध की लंबी अवधि की स्थिति में रक्षा भंडार बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों में कम लागत वाले इंटरसेप्टर और बहु–स्तरीय रक्षा प्रणालियों की भूमिका बढ़ने की संभावना है।विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में खाड़ी क्षेत्र में रक्षा निवेश और हथियारों की खरीद में तेजी आ सकती है। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए लेजर–निर्देशित कम लागत वाली मिसाइल प्रणालियों, अतिरिक्त सेंसर नेटवर्क और सैटेलाइट आधारित निगरानी तंत्र की आवश्यकता बढ़ेगी। इसके साथ ही खाड़ी देश अपने हथियारों के स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के अलावा चीन और रूस जैसे विकल्पों पर भी ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि इनके ईरान के साथ संबंध इस संतुलन को जटिल बनाते हैं। दानिया जफर का मानना है कि इसके बावजूद अमेरिका खाड़ी सुरक्षा संरचना की रीढ़ बना रहेगा। वहीं हमाद अल–थुनिन के अनुसार जब तक आर्थिक और सामरिक हित साझा रहेंगे, तब तक अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच रणनीतिक संबंध जारी रहेंगे।

यूक्रेन का अनुभव भी बन सकता है उपयोगी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में संकेत दिया कि मध्य–पूर्व के कई देशों ने हवाई रक्षा प्रणालियों के अनुभव साझा करने के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है। उनके अनुसार आधुनिक युद्ध में केवल पारंपरिक रक्षा प्रणालियां पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है।

बदलती सुरक्षा रणनीति की ओर बढ़ते खाड़ी देश

मौजूदा परिस्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खाड़ी देशों को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बहु–स्तरीय रणनीति अपनानी होगी। इसमें क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना, रक्षा तकनीक में निवेश बढ़ाना और वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित साझेदारी बनाए रखना शामिल होगा। संभव है कि आने वाले वर्षों में खाड़ी देशों की सुरक्षा नीति केवल बाहरी सहयोग पर आधारित न रहकर क्षेत्रीय समन्वय, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक संतुलन के नए मॉडल की ओर बढ़े। यही मॉडल इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा का भविष्य तय कर सकता है।

-Courtesy-
BBC.com Hindi

अमेरिका-ईरान युद्ध 50 अरब डॉलर का संकट

विकास पारिक
विदेश प्रतिनिधि, लंदन

२८ फरवरी २०२६ को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य हमला कर दिया। इस एक निर्णय ने न केवल मध्य–पूर्व को बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों भारतीय परिवारों के जीवन को सीधे प्रभावित कर दिया। यह युद्ध अब अपने ३४वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है। खाड़ी देशों में ६१ लाख भारतीय प्रवासी निवास करते हैं। ये वे वीर पुरुष और महिलाएँ हैं जिन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी मिट्टी छोड़कर विदेश में काम किया और हर वर्ष ४ लाख करोड़ से अधिक की विदेशी मुद्रा भारत भेजी। यह राशि न केवल उनके परिवारों का सहारा है, बल्कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रीढ़ भी है। खाड़ी में काम करने वाला हर भारतीय अपने पीछे चार से पाँच लोगों का पेट पालता है। ४ से ५ करोड़ भारतीय सीधे इस रोजगार पर निर्भर हैं। पूर्व भारतीय राजदूत, सऊदी अरब यह संकट केवल आर्थिक नहीं है यह भारत की रणनीतिक ताकत, हमारी सभ्यतागत पहचान और हमारे प्रवासियों के प्रति राष्ट्र के कर्तव्य की परीक्षा है। एक हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टि से, यह समय है जब भारत को मौन तोड़कर अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय देना होगा। खाड़ी में भारतीय डायस्पोरा केवल एक संख्या नहीं है यह भारत का सबसे बड़ा अनौपचारिक राजनयिक नेटवर्क है। संयुक्त अरब अमीरात में ३५ लाख, सऊदी अरब में २५ लाख, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर में और लाखों भारतीय ये सभी मिलकर एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो पाकिस्तान की पूरी प्रवासी संख्या से लगभग दोगुना है। यह तथ्य स्वयं में भारत की सॉफ्ट पावर का प्रमाण है। ये प्रवासी निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक हों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बैठे भारतीय पेशेवर दोनों ने खाड़ी के विकास में अपना खून–पसीना बहाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दुबई की ऊंची इमारतें खड़ी कीं, रियाद के अस्पताल चलाए, और कतर के तेल क्षेत्रों में काम किया। अब जब ईरान के प्रतिशोधात्मक हमले खाड़ी देशों पर हो रहे हैं, तो इन ६१ लाख भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार दोनों खतरे में हैं। कई भारतीय श्रमिकों ने अल जजीरा को बताया मुझे डर है कि युद्ध बढ़ा तो नौकरी चली जाएगी। घर में चार लोग मुझ पर निर्भर हैं।

वर्ष २०२४–२५ में खाड़ी देशों से

भारत आने वाला प्रेषण (remittance) लगभग ५० अरब अमेरिकी डॉलर यानी ४.२ लाख करोड़ था। यह धन सीधे उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों के गाँवों और कस्बों में जाता है। इस धन से बच्चों की फीस भरी जाती है, बेटियों की शादी होती है, बुजुर्ग माँ—बाप का इलाज होता है, और खेत के लिए ट्रैक्टर खरीदा जाता है। यह केवल श्विदेशी मुद्राश नहीं है यह करोड़ों भारतीय परिवारों की साँसें हैं। जब होर्मुज बंद होता है, तो दुबई का भारतीय मजदूर डरता है। जब वह डरता है, तो उसके गाँव का घर काँपता है। भारतीय रुपया ६४.७८ प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुँच चुका है। शेयर बाजार लगातार पाँचवें सप्ताह गिर रहा है। GDP वृद्धि दर पर खतरा मंडरा रहा है। यह केवल संख्याएँ नहीं हैं यह उन परिवारों की तकलीफ है जो खाड़ी से आने वाले पैसों पर जीते हैं। यदि युद्ध और भड़का, तो ६१ लाख भारतीयों की निकासी इतिहास का सबसे बड़ा नागरिक बचाव अभियान होगा। तुलना के लिए ऑपरेशन सुकून (२००६, लेबनान) में भारत ने मात्र दो हजार नागरिकों को निकाला था। ऑपरेशन राहत (२०१५, यमन) में लगभग ४,७०० लोगों को सुरक्षित किया गया था। लेकिन खाड़ी में ६१ लाख? यह संख्या पिछले सभी बचाव अभियानों से ६० गुना बड़ी है। भारतीय नौसेना और वायुसेना के पास इतनी क्षमता नहीं है। यह स्वयं में एक राष्ट्रीय सुरक्षा विफलता का संकेत है जिसे अब ठीक करना होगा। ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना को स्व्छ और कच्चे तेल के टैंकरों की सुरक्षा के लिए स्टैंडबाय पर रखा गया है। यह एक सराहनीय कदम है परंतु पर्याप्त नहीं। राष्ट्र की माँग है कि एक विस्तृत प्रवासी सुरक्षा नीति तत्काल घोषित की जाए। भारत ने आधिकारिक रूप से इस युद्ध में तटस्थता की घोषणा की है। परंतु तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध शुरू होने से मात्र दो दिन पहले तेल अवीव का दौरा किया। यह श्संयोगश नहीं था यह एक रणनीतिक संदेश था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से, भारत की यह श्मौन तटस्थताश वास्तव में अमेरिका और इजरायल के प्रति झुकाव को दर्शाती है। एक ओर हम रूस यूक्रेना युद्ध में बहु ध्रुवीय विश्व की वकालत करते थे वहाँ हमने रूस का साथ नहीं छोड़ा। परंतु यहाँ, ईरान की संप्रभुता पर हमले पर भारत मौन क्यों? श्हर संस्थापक सदस्य रूस, चीन, ब्राजील ने युद्ध की निंदा की। केवल भारत ने अपनी चुप्पी से इसे मंजूरी दी। कपिल कोमिरेड्डी, अनहर्ड। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि भारत BRICS का वर्तमान अध्यक्ष है। ईरान ने BRICS हस्तक्षेप के लिए भारत से विनती की परंतु मोदी सरकार ने उस अनुरोध को अनसुना कर दिया। यह न केवल कूटनीतिक अवसर की हानि है, बल्कि भारत की विश्व गुरु छवि पर धक्का भी है। राष्ट्रवादी माँगरू भारत को तटस्थता का नाटक छोड़कर वास्तविक मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपमान यह है कि इस युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है! वही पाकिस्तान जो आतंकवाद का निर्यातक है, जो कंगाल है, जो IMF की भीख पर जीता है वह आज वैश्विक मंच पर शांतिदूत बनकर उभर रहा है। राहुल गाँधी ने इसे श्मोदी की विदेश नीति का मजाक कहा और इस बार वे गलत नहीं हैं। जब भारत के ६१ लाख नागरिक खाड़ी में फँसे हैं, जब ४ लाख करोड़ की विप्रेषण पर खतरा है, जब भारत BRICS का अध्यक्ष है तब भी यदि हम चुप रहें, तो यह राष्ट्रीय कायरता है। भारत की क्षमता है, संसाधन हैं, इतिहास है परंतु जब तक नेतृत्व में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हम वैश्विक मंच पर वह स्थान नहीं पाएँगे जो हमारा अधिकार है। भारत को तुरंत अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ उच्च—स्तरीय वार्ता करनी चाहिए। BRICS अध्यक्षता का उपयोग करते हुए एक आपातकालीन शांति प्रस्ताव लाया जाए। सरकार को तत्काल एक ५०, ००० करोड़ का भारतीय प्रवासी आपात कोष बनाना चाहिए जो संकट में फँसे भारतीयों की निकासी, पुनर्वास और रोजगार की गारंटी दे। यह संकट हमें याद दिला रहा है कि भारत की ६०ः से अधिक ऊर्जा जरूरतें आयात पर निर्भर हैं। सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंद महासागर में भारत की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए नौसेना के आधुनिकीकरण में निवेश को तत्काल दोगुना किया जाए। प्ैै क्मदं जैसी घटनाएँ भारतीय समुद्री क्षेत्र में दोबारा न हों। अमेरिका—ईरान युद्ध एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है यह वैश्विक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का क्षण है। इस क्षण में जो राष्ट्र सक्रिय रहेगा, वह नई विश्व व्यवस्था में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। जो मौन रहेगा, वह इतिहास की धारा में बह जाएगा। भारत के ६१ लाख प्रवासी केवल कमाई करने वाले श्रमिक नहीं हैं वे भारत माता के वीर पुत्र—पुत्रियाँ हैं जिन्होंने विदेश की धरती पर भी तिरंगे की शान बनाए रखी। उनकी रक्षा करना, उनकी वापसी सुनिश्चित करना, और उनके परिवारों की आजीविका बचाना यह भारत सरकार का नैतिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारत तब महान था, जब वह विश्व का नेतृत्व करता था। भारत तब महान होगा, जब वह फिर से वही करेगा। यह समय मौन का नहीं शंखनाद का है।

ऊर्जा संकट की असल चुनौती अभी बाकी है

प्रभात कुमार रॉय
पूर्व नौकरशाह

ईरान के विरुद्ध इजरायल–अमेरिका द्वारा 28 फरवरी को प्रारंभ किया गया संयुक्त आक्रमणकारी युद्ध विगत एक महीने से अपनी संपूर्ण विनाशकारी सैन्य शक्ति के साथ निरंतर जारी है। यदि यह विनाशकारी युद्ध भविष्य में भी इसी गति से चलता रहा तो फिर पहले से आच्छादित हो चुका वैश्विक ऊर्जा संकट अत्यंत विकट और विकराल स्थिति में पहुंच जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिनों के लिए और फिर 10 दिनों के लिए ईरान के ऊर्जा उपक्रमों पर विध्वंसकारी आक्रमण अंजाम नहीं देने का ऐलान किया है। साथ ही यह चेतावनी भी जारी की है कि यदि ईरान द्वारा भविष्य में खाड़ी देशों के ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर ईरान द्वारा आक्रमण किया जाता है तो फिर अमेरिका ईरान के गैस और तेल निर्माण के ठिकानों परपर भयंकर आक्रमण अंजाम देगा और उसके तमाम ऊर्जा उपक्रमों को नष्ट कर देगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा पेश किया है कि ईरान के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता निरंतर जारी है। युद्ध के कारणवश उत्पन्न हुई वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते हुए भारत पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव स्थापित हो गया है। फिलहाल भारत में पेट्रोल और डीजल का तो कोई तत्काल संकट उपस्थित नहीं हुआ है। क्योंकि भारत सरकार के अनुसार अभी दो महीनों का पेट्रोल और डीजल स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पर भारत के पास विद्यमान है। किंतु कतर का लिक्विड नेचुरल गैस उत्पादन एकदम बंद हो जाने के कारण भारत में लिक्विड नेचुरल गैस और एलपीजी का संकट अवश्य उत्पन्न हो गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट के मध्य एक शुभ समाचार आया कि अमेरिका ने ईरान के क्रूड ऑयल निर्यात पर आयद की गई अंतरराष्ट्रीय पाबंदी को अस्थाई तौर पर स्थूल कर देने का ऐलान किया है। अमेरिका के वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में फरमाया है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा फिलहाल समुद्र में खड़े हुए ईरान के तेल जहाज पर आयद पाबंदी में अस्थाई तौर पर ढील प्रदान करने का फैसला लिया है। अमेरिका द्वारा ईरानी तेल पर आयद पाबंदी में तत्कालीन ढील प्रदान करने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों बैरल तेल की सप्लाई प्रारंभ हो सकती है और इस युद्ध के कारण शिपिंग और क्रूड ऑयल निर्यात में उत्पन्न हुई गंभीर रुकावट की क्षतिपूर्ति भी हो सकती है। अमेरिका द्वारा फिलहाल ईरानी तेल के निर्यात पर पाबंदी समाप्त कर देने का सबसे अधिक फायदा जिन देशों को भविष्य में उपलब्ध हो सकता है, उनमें भारत भी एक प्रमुख देश है। खाड़ी जंग प्रारंभ होने के बाद विश्व पटल पर एनर्जी मार्केट पर जबरदस्त संकट बढ़ गया है और अमेरिका द्वारा समुद्र में कार्गो जहाज में विद्यमान ईरानी तेल के निर्यात से यह विकट संकट कुछ कम हो सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत को अपनी आवश्यकता के 90 प्रतिशत पेट्रोल और डीजल के लिए अंतरराष्ट्रीय आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अमेरिका के वित्त मंत्री

करने का बाकायदा अनुभव और तकनीक उपलब्ध रही है। देखना है कि विश्व पटल पर भारत वस्तुत क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाला सबसे बड़ा चौथा देश है। क्रूड तेल और गैस सप्लाई में विकेट बधाओं का सामना करते हुए भी भारत ने चीन की तरह रिफाइन तेल के अंतरराष्ट्रीय निर्यात पर रोक आयद नहीं की है। हालांकि भारत के समक्ष भी ऊर्जा संकट की कड़ी चुनौतियां विद्यमान हैं। ईरानी तेल पर पाबंदियां अस्थाई तौर पर ढीली करने से पहले अंतरराष्ट्रीय रूप से क्रूड ऑयल की सप्लाई जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय मूल्य को नियंत्रित करने की गरज से अमेरिका द्वारा पहले ही रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी करने के लिए आयद की गई पाबंदियां को तीस दिनों के लिए समाप्त कर दिया गया था। युद्ध के निरंतर जारी रहते हुए, संभव है कि रूसी तेल से खरीदारी करने पर आयद पाबंदियों को और अधिक काल के लिए अमेरिका द्वारा बढ़ा दिया। जाए। फिलहाल तो भारत के सामने पेट्रोल और डीजल की समुचित सप्लाई का कोई तत्कालीन संकट उपस्थित नहीं है, किंतु अगर युद्ध इसी गति से जारी रहता है तो फिर भारत में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर विकट संकट संकट का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर आयद पाबंदियों को ढीला करने के लिए अमेरिका के वित्त मंत्री स्काट बेसेंट के ऐलान को अमलीजामा पहनाने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि उनके ऐलान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्पष्ट ऐलान नहीं किया गया है।

स्कॉट बेसेंट के अनुसार समुद्र में फिलहाल अभी 17 करोड़ बैरल तेल के कार्गो विद्यमान हैं। भले ही ईरानी क्रूड ऑयल की अंतरराष्ट्रीय बिक्री के लिए 10 से 15 दिनों तक छूट क्यों ना प्रदान की जा सकती है। अमेरिकन खरीदारों तक इसके पहुंच की मंजूरी प्रदान करने से क्रूड ऑयल सप्लाई की दिक्कतें कम होने और कीमतों को नियंत्रित करने में निश्चित तौर पर निर्णायक मदद मिल सकती। अमेरिकन वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार इस कदम से ईरान का जो तेल चीन में जा रहा है, वो क्रूड ऑयल दूसरे एशियाई देशों की तरफ भी अपना रुख मोड़ सकता है। जिससे चीन को बाजार दर पर तेल खरीदना पड़ सकता है। साथ ही साथ भारत, जापान, मलेशिया, फिलिपींस आदि दक्षिण एशिया के देशों के लिए क्रूड ऑयल उपलब्ध हो सकेगा। चीन अभी तक ईरानी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। फिलहाल तो भारत की रिफाइनरियों ने समुद्र में विद्यमान कार्गो जहाजों पर लदे हुए लाखों बैरल रूसी क्रूड ऑयल को ही खरीदा है। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा आयातित क्रूड आयल का तकरीबन 60 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी मुल्कों से आता रहा है। इन मुल्कों में इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात मुख्यतः शामिल हैं। खाड़ी देशों से आयातित होने वाले क्रूड ऑयल का अधिकांश हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। फिलहाल युद्ध के जारी रहते हुए होर्मुज स्ट्रेट से कार्गो जहाजों की आवाजाही अत्यंत बाधित हो चुकी है। सन् 2018 में ईरान पर सख्त अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां आयद किए जाने से पहले तक भारत द्वारा कुल आयातित क्रूड ऑयल का तकरीबन 15 प्रतिशत हिस्सा ईरान से आयात किया जाता था। अमेरिकन वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक इस वक्त तकरीबन ईरान का 17 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल समुद्र में कार्गो शिप्स पर विद्यमान है। ईरान का यह समस्त तेल पहले से अनुबंधों कदाचित बंधा हुआ नहीं है। ईरानी क्रूड ऑयल का एक हिस्सा इस समय विक्रय के लिए तैयार है। अगर अमेरिका द्वारा इन पाबंदियों को ढीला कर दिया जाता है अथवा उनका शक्ति से पालन नहीं होता तो फिर इस क्रूड ऑयल की अतिरिक्त सप्लाई अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आ सकती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिफायनरियां ईरानी तेल को अपने सिस्टम में लाने के लिए सक्षम रही हैं और उसके प्रोसेसिंग के लिए बहुत कम ऑपरेशन बदलाव की आवश्यकता उत्पन्न होगी। क्योंकि भारतीय रिफायनरियों के पास पहले से ही ईरानी क्रूड ऑयल को प्रोसेस

‘हम रातभर आसमान से गिरती मिसाइलें देखते थे’ ईरान से भारत लौटे जहाजियों की आपबीती

पिछले साल आठ दिसंबर को ईरानी अधिकारियों ने जिस समुद्री जहाज एमटी वैलेंट रोर को अपने कब्जे में लिया था, उसके चालक दल के आठ भारतीय सदस्य रविवार तड़के भारत वापस पहुंच गए. बीते साल आठ दिसंबर को यूएई के डिब्बा बंदरगाह के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से पकड़े गए इस जहाज में कुल 16 भारतीय कर्मचारी मौजूद थे.

इनमें से आठ कर्मचारियों की भारत वापसी दस फरवरी को हो चुकी थी लेकिन बाकी आठ कर्मचारी 27 फरवरी को रिहा होने के बाद भी घर न लौट सके. ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले की वजह से जहाज के कप्तान सहित शेष आठ जहाजी संघर्षपूर्ण हालात में आर्मीनिया के रास्ते 29 मार्च को भारत पहुंचे. एक वक्त उम्मीद खो चुके ये जहाजी वापस भारत पहुंचने के बाद अब नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और हां एक की तो जल्द शादी भी होने वाली है. बीबीसी न्यूज हिंदी से फोन पर बात करते हुए इन जहाजियों ने ईरान में गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए बेहद मुश्किल हालात के बारे में बताया.

लगा कि कभी भारत नहीं पहुंच पाएंगे

ईरानी अधिकारियों ने 6000 मीट्रिक टन अवैध डीजल ले जाने के आरोप में समुद्री जहाज एमटी वैलेंट रोर को डिब्बा बंदरगाह के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से अपने कब्जे में ले लिया था और इसके 18 क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया था. इस जहाज के कप्तान विजय ने बताया कि यूएई के डिब्बा बंदरगाह के निकट अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में जहाज पर अचानक फायरिंग शुरू हो गई थी. बाद में उन्हें पता चला कि ये कार्रवाई ईरानी सुरक्षा बल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने की है. इसके बाद ईरानी सुरक्षा बल इस जहाज को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक ले गए. उन्होंने दावा किया कि उस दौरान ईरानी अधिकारियों ने जहाज के सभी कर्मचारियों से उनके पैसे, सामान, मोबाइल, लैपटॉप, सारे कपड़े, पासपोर्ट और यहां तक कि उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिए. कप्तान विजय ने कहा, हमसे कई दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया लेकिन हमने मना कर दिया. इस जहाज के 18 क्रू मेंबर्स में से 16 भारतीय

Ship Captain

थे. इनमें से 10 को जेल भेज दिया गया और छह को ईरानी गार्ड्स की कड़ी निगरानी में जहाज के मेस रूम में 27 फरवरी तक नजरबंद रखा गया. चालक दल के सदस्यों का कहना है कि उन्हें बेहद खराब स्थिति में वहां रखा जा रहा था. फोन पर हुई बातचीत में जहाज के सेकेंड इंजीनियर राजशेखर डूंगा ने भावुक होते हुए कहा, राशन न होने पर हम नमक के साथ चावल खाते और इंडस्ट्रियल वाटर जो पीने योग्य नहीं था, उसे उबाल कर पीते. इस बीच चालक दल के परेशान परिजनों ने जनवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा, जिसका जवाब विदेश मंत्रालय ने 20 जनवरी को दाखिल किया. जवाब में कहा गया कि स्थिति पर विदेश मंत्रालय लगातार नजर रखे हुए है और गिरफ्तार क्रू को काउंसलर एक्सेस दिया गया है. जहाजी सतीश के अनुसार भारतीय दूतावास ने काउंसलर एक्सेस जनवरी के दूसरे हफ्ते में उपलब्ध करवाया. बीबीसी हिंदी से बात करते हुए इन जहाजियों ने बताया कि काउंसलर एक्सेस मिलने से पहले ऐसा लगता था कि कभी वापस अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कई लोग ऐसी ही परिस्थितियों में सालों से जहाजों में फंसे हुए थे.

रिहा तो हो गए लेकिन...

10 फरवरी को आठ कर्मचारी रिहा होकर भारत पहुंचे. लेकिन जेल में रह रहे दिल्ली के केतन मेहता, उत्तर प्रदेश के अनिल कुमार सिंह, हरियाणा के सतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के वेंकट राव और बिहार के मसूद आलम को रिहाई नहीं मिली. उन्होंने बताया कि ईरानी गार्ड्स उन्हें जहाज पर वापस ले आए. जहां पहले से ही उत्तर प्रदेश के कप्तान विजय, आंध्र प्रदेश के राजशेखर डूंगा और नंदकी वेंकटेश नजरबंद थे. अनिश्चितता, भय और कठिनाइयों का सामना कर रहे इन लोगों को रिहाई का आदेश 27 फरवरी की शाम को मिला.

रिहाई का आदेश मिलने के बाद भारतीय दूतावास ने हस्तक्षेप कर ईरानी गार्ड्स से सभी आठ कर्मचारियों को पासपोर्ट वापस दिलवाया. इससे इन लोगों को महसूस हुआ कि वह आखिरकार आजाद हो गए हैं लेकिन रात होते ही इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया. जहाज के कप्तान विजय कुमार कहते हैं, युद्ध के कारण रिहाई के आदेश की खुशी कुछ घंटे तक भी बरकरार न रह सकी थी. इसराइल–अमेरिका और ईरान युद्ध के साथ ही ईरान के बॉर्डर और हवाई अड्डे से आवाजाही रुक गई और इसकी वजह से रिहाई के बाद भी ये भारत नहीं लौट पा रहे थे.

बंदर अब्बास में इन लोगों का जहाज ईरानी नौसेना बेस के बिलकुल नजदीक मौजूद था. ऐसे में जंग शुरू होने के कारण सभी को एक नई चिंता ने घेर लिया. कप्तान विजय ने बताया कि वह चाहकर भी जहाज

होटल, कैब, आदि का खर्च व हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी के मालिक की थी. लेकिन उनका रिस्पॉन्स न मिलना हम लोगों के लिए निराशाजनक रहा. वह बताते हैं कि भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप पर कंपनी ने सिर्फ बंदर अब्बास के होटल का खर्च वहन किया, जबकि जॉल्फा के होटल का खर्च दूतावास ने वहन किया. आर्मीनिया पहुंचने पर जो होटल लिया उसका खर्च क्रू ने खुद वहन किया.कप्तान विजय से सहमत मसूद आलम कहते हैं कि ष्हम सभी क्रू की कई महीने की पेमेंट अदा नहीं हुई है. बताइए हम दोबारा इस कंपनी के शिप में जाने की हिम्मत कैसे करेंगे?

को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे क्योंकि जहाज के सारे नेविगेशन उपकरण पहले ही ईरानी अधिकारी हटा चुके थे. वह कहते हैं, ऐसे में हम रातभर असहाय होकर आसमानों से आती मिसाइलों को देखते रहे. जो हमारे आसपास गिर रही थीं. कैप्टन विजय ने कहा कि उन्होंने अपनी कंपनी को इस स्थिति से अवगत भी कराया कि उनके पास आग से निपटने के या जीवनरक्षक उपकरण नहीं हैं. लेकिन कंपनी का आदेश था कि वे सभी जहाज पर रहें. बीबीसी न्यूज हिन्दी ने कैप्टन विजय के इस आरोप के बारे में कंपनी के मालिक जोगविंदर बराड़ से सम्पर्क किया लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया. तीन मार्च की रात भारतीय दूतावास ने सभी को रेस्क्यू करवाकर बंदर अब्बास के एक होटल में शरण दिलवाई. केतन मेहता कहते हैं कि वहां भी आस–पास के मलबे देखकर दिन में नींद नहीं आती और रात भी मिसाइलों के खौफ में ही गुजरती. केतन मेहता की बात को बीच में ही काटते हुए चीफ इंजीनियर अनिल कुमार सिंह कहते हैं, ष्पचास साल की उम्र तक मैंने कभी दुख, तकलीफ, खौफ का कोई मंजर नहीं देखा. लेकिन इस सफर में हमारा एक–एक पल मौत के एकदम नजदीक से गुजरा. भारतीय क्रू के अनुसार हालात ऐसे थे कि आस–पास होती बमबारी के कारण रातभर उनके होटल की दीवारें भयंकर रूप से कंपन करतीं. उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनिल कुमार सिंह बताते हैं कि तीन से लेकर 11 मार्च तक हालात बद से बदतर रहे, लेकिन 11 मार्च के बाद हमलों में कमी आ गई.

बिन पैसे के दो देशों की यात्रा

15 मार्च को भारतीय दूतावास ने कैप्टन विजय को आर्मीनिया बॉर्डर के खुलने की सूचना दी. चालक दल के सदस्यों ने बताया कि गिरफ्तारी के समय इनके पैसे–कपड़े सब कुछ ईरानी अधिकारियों ने ले लिए थे इसलिए वापस लौटने के लिए इन्हें कहीं से उधार पैसे का इंतजाम करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने एक कैब की. सफर के दौरान वह एक ऐसे इलाके से भी निकले जहां बमबारी हो रही थी. आर्मीनिया बॉर्डर से लगभग 60 किलोमीटर पहले ईरान के जॉल्फा में उन्हें ठहरना पड़ा. तीन दिन के इंतजार के बाद सभी को आर्मीनिया का वीजा मिला. 27 मार्च को ये आर्मीनिया की राजधानी येरेवान पहुंचे. वहां सभी ने एयरपोर्ट के नजदीक एक होटल में रात गुजारी. 28 मार्च की शाम ये सभी दुबई पहुंचे. जहां से 29 मार्च की सुबह पांच बजे ये लोग मुंबई पहुंचे. चालक दल के सदस्यों ने बताया कि इन उड़ानों के लिए डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया की पहल से सभी को फ्लाइट की टिकट उपलब्ध हुई. कप्तान विजय कहते हैं कि ष्ईरानी नियंत्रण के दौरान शिप पर खाने से लेकर तमाम जरूरी चीजें, वकील,

खूंखार अपराधियों संग कैद से शादी की तैयारियों तक

मसूद का मानना है कि ये सफर एक ऐसी हकीकत है जिससे उबर पाना बहुत मुश्किल है. वह कहते हैं, हमें ईरानियों ने रेप, ड्रग्स तस्करी, हत्या के संगीन अपराधियों के बीच रखा. जो बहुत कष्टदाई था, क्योंकि हम सभी बेकसूर थे. जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं. इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी की है. हालांकि भारत वापस आने के बाद ये सभी जहाजी बेहद राहत महसूस कर रहे हैं. मसूद की ईद के बाद शादी होनी थी, जो एक बार तो जैसे खटाई में ही पड़ गई थी... लेकिन अब उम्मीद और उमंग लौट आई है. शादी की नई तारीख तय की जा रही है और उनके घर में नए सिरे से तैयारियां शुरू हो गई हैं. बीबीसी हिंदी से बातचीत में मसूद के बहनोई ने खुश होकर बताया कि आजकल सब लोग शादी के लिए खरीदारी में व्यस्त हैं.

-Courtesy-
BBC.com Hindi

नालको वित्त वर्ष 2025–26 : उत्पादन और बिक्री के सभी पुराने रिकॉर्ड टूटे

भारत सरकार के खान मंत्रालय के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने वित्त वर्ष 2025–26 में अपने चार दशक से अधिक लंबे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करते हुए उत्पादन और बिक्री दोनों मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कंपनी ने कई प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में अब तक का सर्वोच्च उत्पादन हासिल किया, जिससे एल्यूमिना और एल्यूमिनियम क्षेत्र में एक एकीकृत अग्रणी कंपनी के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

उत्पादन के क्षेत्र में बने नए रिकॉर्ड

वित्त वर्ष 2025द्26 के दौरान नालको ने उत्पादन के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। कंपनी ने 77.01 लाख टन बॉक्साइट उत्खनन और 77.07 लाख टन बॉक्साइट परिवहन दर्ज किया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। इसके साथ ही एल्यूमिना हाइड्रेट उत्पादन 23.00 लाख टन और कैल्साइंड एल्यूमिना उत्पादन 22.75 लाख टन रहा, जो कंपनी के इतिहास का सर्वाधिक उत्पादन है। इसी अवधि में कास्ट एल्यूमिनियम धातु उत्पादन 4.72 लाख टन तक पहुंच गया, जबकि शुद्ध विद्युत उत्पादन 6,953 मिलियन यूनिट और कोयला उत्पादन 40 लाख टन दर्ज किया गया, जो कंपनी की परिचालन क्षमता में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।

बिक्री के मोर्चे पर भी शानदार प्रदर्शन

उत्पादन के साथ–साथ बिक्री के क्षेत्र में भी नालको ने उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज कीं। वित्त वर्ष 2025द्26 में कंपनी की कुल एल्यूमिना बिक्री 14.46 लाख टन रही, जबकि घरेलू एल्यूमिना बिक्री 1.38 लाख टन दर्ज की गई। इसी तरह एल्यूमिनियम धातु की कुल बिक्री 4.74 लाख टन रही, जिसमें घरेलू बाजार में 4.61 लाख टन की अब तक की सर्वाधिक बिक्री शामिल है।

पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि

कंपनी के प्रदर्शन में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। बॉक्साइट परिवहन में 6.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कैल्साइंड एल्यूमिना उत्पादन में 11.16 प्रतिशत और कास्ट एल्यूमिनियम धातु उत्पादन में 2.61 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिक्री के क्षेत्र में कुल एल्यूमिना बिक्री में 30.74 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई, जबकि कुल एल्यूमिनियम बिक्री में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। नालको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Brijendra Pratap Singh ने कंपनी के इस प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अनुगुल में आयोजित वार्षिक व्यापार योजना रणनीतिक बैठक के दौरान उन्होंने पूरी टीम और सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कंपनी लगातार अपने ही स्थापित मानकों को पार करने की दिशा में काम कर रही है और यह उपलब्धि भविष्य में व्यावसायिक उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने का मजबूत आधार तैयार करती है। भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नालको अपनी उत्पादन क्षमताओं के विस्तार के साथ–साथ संयंत्र दक्षता, मानव संसाधन दक्षता और प्रक्रिया दक्षता पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही डिजिटल परिवर्तन को अपनाने और हरित पहल को आगे बढ़ाने पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। उन्होंने इस उपलब्धि में सहयोग के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार और ओडिशा सरकार के मार्गदर्शन और समर्थन को भी महत्वपूर्ण बताया।

वैश्विक एल्यूमिनियम उद्योग में मजबूत हुई नालको की स्थिति

वित्त वर्ष 2025द्26 के रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ नालको ने न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच परिचालन उत्कृष्टता का नया मानक स्थापित किया है, बल्कि वैश्विक एल्यूमिनियम उद्योग में भी अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है। कंपनी का यह प्रदर्शन सतत विकास, बेहतर प्रबंधन और मजबूत उत्पादन क्षमता का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

प्रस्तुति
प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

कृष्ण कुमार सिंह बने सेल के अंतरिम चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निदेशक (कार्मिक) कृष्ण कुमार सिंह ने 2 अप्रैल 2026 को कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। स्थायी नियुक्ति होने तक वे यह जिम्मेदारी अंतरिम रूप से निभाएंगे। इस बीच, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने सेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद के लिए डॉ. अशोक कुमार पांडा के नाम की सिफारिश की है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद डॉ. पांडा आधिकारिक रूप से इस पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। करीब चार दशकों के अनुभव के साथ कृष्ण कुमार सिंह सेल के संचालन, मानव संसाधन विकास, सतर्कता तथा कार्मिक एवं प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1987 में भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में की थी। प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने 'ब्लूमिंग एंड बिलेट मिल' में एक दशक से अधिक समय तक कार्य किया, जिसके बाद मानव संसाधन विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में कार्यकारी निदेशक (प्रभारी) सहित कई महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों पर काम किया। वर्ष 2022 में उन्हें निदेशक (कार्मिक) नियुक्त किया गया, जो उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण माना जाता है। निदेशक (कार्मिक) के रूप में उन्होंने सेल में मानव संसाधन प्रणाली को मजबूत बनाने और कार्यबल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू कीं। उनके नेतृत्व में कर्मचारियों के कल्याण, प्रशिक्षण और विकास से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा मिली है। अंतरिम रूप से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए कृष्ण कुमार सिंह से उम्मीद की जा रही है कि वे संगठन को परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और जन–केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राजेश कुमार बने आरईसी के नए वित्त निदेशक

राजेश कुमार ने 2 अप्रैल 2026 को आरईसी लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले 25 मार्च 2026 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उन्हें इस पद पर पाँच वर्षों के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की थी।

राजेश कुमार सार्वजनिक क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव रखने वाले वरिष्ठ वित्त विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से पावर और अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में उनकी गहरी विशेषज्ञता रही है। उन्हें लेखांकन, कराधान, लेखा परीक्षण, ट्रेजरी प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन तथा नियामकीय अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने Shri Ram College of Commerce] University of Delhi से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और वे चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोनों पेशेवर योग्यताएँ रखते हैं। इस नियुक्ति से पूर्व वे आरईसी लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने संस्थान की वित्तीय रणनीतियों को मजबूत बनाने और संसाधन जुटाने की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने करियर के शुरुआती चरण में उन्होंने एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ इंजीनियरिंग एवं परियोजना परामर्श सेवाओं में लगभग दस वर्षों तक कार्य किया, जिसके बाद आरईसी लिमिटेड में दो दशकों से अधिक समय तक निरंतर सेवाएँ दीं और पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में विशेष दक्षता विकसित की। राजेश कुमार REC Power Development and Consultancy Limited के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं तथा स्मार्ट मीटरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व किया। आरईसी लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जटिल वित्तीय पोर्टफोलियो के प्रभावी प्रबंधन और संसाधन जुटाने के नवाचारपूर्ण उपायों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टैक्स–एफिशिएंट हाइब्रिड बॉन्ड, एएए रेटिंग वाले परपेचुअल बॉन्ड, सीबीडीटी–अधिसूचित जीरो कूपन बॉन्ड तथा कैपिटल गेन बॉन्ड जैसे नवोन्मेषी बॉन्ड संरचनाओं को अपनाया गया, जिससे कंपनी के निवेशक आधार का विस्तार हुआ और उधारी लागत में कमी आई। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुपक्षीय वित्तपोषण, एसेट–लायबिलिटी प्रबंधन, ईएसजी परियोजनाओं तथा आईटी परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलों का भी रणनीतिक नेतृत्व किया। जटिल कर मामलों के समाधान में भी उनके प्रयासों से संगठन को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ।

प्रस्तुति
प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

ऊर्जा क्षेत्र में एसजेवीएन की मजबूत बढ़त, वार्षिक उत्पादन में बना नया रिकॉर्ड

एसजेवीएन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान अपने प्रचालनरत विद्युत स्टेशनों से कुल 13,302 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Bhupendra Gupta ने बताया कि यह प्रदर्शन संगठन की मजबूत परिचालन क्षमता और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन'' ने 7,506. 617 मिलियन यूनिट उत्पादन के साथ अपना दूसरा सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन दर्ज किया और मार्च 2026 में ''150 बिलियन यूनिट संचयी उत्पादन'' का आंकड़ा पार किया। वहीं ''412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत स्टेशन'' ने 2,108. 034 मिलियन यूनिट उत्पादन कर अपने इतिहास का सर्वोच्च स्तर हासिल किया। इसके अलावा ''60 मेगावाट नैटवार मोरी जलविद्युत स्टेशन'' ने 310.37 मिलियन यूनिट उत्पादन दर्ज किया, जो इसकी डिजाइन क्षमता से लगभग ''17: अधिक'' है। साथ ही ''1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना'' ने 19 मार्च 2026 को ''1 बिलियन यूनिट उत्पादन'' का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। निदेशक (कार्मिक) **Ajay Kumar Sharma** और निदेशक (वित्त) Parthajit Dey ने इस उपलब्धि का श्रेय कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और संगठन की सुदृढ़ कार्यक्षमता को दिया। कंपनी ने भारत सरकार के ''2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता'' लक्ष्य में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

भारत-अफ्रीका ऊर्जा साझेदारी को मिला नया आयाम, शिखर सम्मेलन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित

भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन आयोजित भारतदृअफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक में ऊर्जा क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया। इस बैठक में विभिन्न देशों के मंत्री, राजनयिक, वरिष्ठ अधिकारी तथा ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत Jitendra Srivastav, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी लिमिटेड के स्वागत संबोधन से हुई। इसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अफ्रीका–50 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सत्र की रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री तथा विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही मॉरीशस और मलावी के ऊर्जा मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों तथा स्थायी सचिवों ने सक्रिय भागीदारी की। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक समूह, केन्या विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड तथा अफ्रीका अवसंरचना विकास संघ के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा अवसंरचना विकास, निवेश सहयोग तथा क्षमता निर्माण से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष ने भारतीय विद्युत क्षेत्र की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इसके पश्चात भारत और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के बीच संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने, निवेश सहयोग को मजबूत करने तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ़ करने के विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस सत्र में अर्न्स्ट एंड यंग ने ज्ञान सहयोगी तथा संचालन सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह बैठक भारत और अफ्रीकी देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास तथा अवसंरचना सहयोग को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।

प्रस्तुति
प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

भारत विद्युत शिखर सम्मेलन : 2026 में आरईसी-पीएफसी का 'मेक इन इंडिया' सत्र

भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन "विद्युत वितरण के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा" विषय पर एक उच्चस्तरीय विक्रेता विकास सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सत्र का संयुक्त आयोजन आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया, जिसमें विद्युत मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विभिन्न वितरण कंपनियों, उद्योग संगठनों, विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं तथा तकनीकी विशेषज्ञों के बड़ी संख्या में वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सत्र घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने और विद्युत वितरण क्षेत्र में स्वदेशी समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। सत्र की अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वितरण) शशांक मिश्रा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत आरईसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएँ) टी. एस. सी. बोश के स्वागत संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने विद्युत वितरण अवसंरचना के आधुनिकीकरण में स्वदेशी तकनीकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उद्योग प्रतिनिधियों ने भी वितरण क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, उपकरण निर्माण तथा स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। सत्र के दौरान आयोजित परिचर्चा में विद्युत मंत्रालय के निदेशक प्रणव तयाल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक सौरव कुमार शाह तथा आरईसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने भाग लिया। उन्होंने वितरण तंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने, संकुचित उपकेंद्रों के विस्तार, भूमिगत केबल व्यवस्था को प्रोत्साहन देने, वास्तविक समय आँकड़ा प्रणाली के उपयोग तथा मानकीकरण को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किए। साथ ही आयात पर निर्भर सामग्रियों को चरणबद्ध रूप से कम करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया। सत्र का समापन विद्युत मंत्रालय के निदेशक (वितरण) रवि धवन के समापन संबोधन के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तकनीकी उन्नयन और संस्थागत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

केंद्रीय मंत्रियों ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में आरईसी के 'ग्रीन मल्टीप्लायर' पवेलियन का शुभारंभ

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट के दौरान आरईसी लिमिटेड के "ग्रीन मल्टीप्लायर" पवेलियन का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल, आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव तथा मंत्रालय और आरईसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह पवेलियन "भारत की ऊर्जा प्रचुरता का वित्तपोषण" विषय पर आधारित है और सतत ऊर्जा पहलों के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने में आरईसी की भूमिका को प्रदर्शित करता है। इसका आकर्षक स्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा, हरित विकास और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की तेज प्रगति को दर्शाता है। पवेलियन का मुख्य आकर्षण सूर्य और सौर पैनलों की प्रेरक स्थापना रही, जो "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" से प्रेरित है। यह प्रस्तुति विकेंद्रीकृत विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने और आम नागरिकों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाने में आरईसी के योगदान को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त पवेलियन में वर्ष 2070 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में आरईसी के वित्तीय सहयोग, विद्युत अवसंरचना विकास, विद्युत चालित परिवहन तथा समावेशी ऊर्जा परिवर्तन में उसकी सक्रिय भूमिका को भी प्रदर्शित किया गया। उन्नत प्रकाशीय दीवारों, गतिशील प्रदर्शन प्रणालियों और रेडियो आवृत्ति पहचान आधारित प्रस्तुति तकनीकों से सुसज्जित यह पवेलियन आगंतुकों को एक आधुनिक अनुभव प्रदान करता है और भारत के हरित ऊर्जा भविष्य में आरईसी की अग्रणी भूमिका को प्रभावशाली रूप से सामने लाता है।

प्रस्तुति
प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

एसबीआई ने टियर-2 बॉन्ड से 6,051 करोड़ रुपये जुटाए

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पूंजी स्थिति को मजबूत करने के लिए टियर–2 बॉन्ड के माध्यम से 6,051 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस बॉन्ड निर्गम के लिए बोली प्रक्रिया 17 मार्च 2026 को आयोजित की गई, जिसमें निवेशकों की ओर से उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली। इस निर्गम के तहत 6,051 गैर–परिवर्तनीय, करयोग्य, विमोचनीय, अधीनस्थ और असुरक्षित बॉन्ड जारी किए गए, जिनमें प्रत्येक बॉन्ड का अंकित मूल्य 1 करोड़ रुपये रखा गया। इन बॉन्ड पर 7.05 प्रतिशत वार्षिक कूपन दर निर्धारित की गई, जो राष्ट्रीय स्तर के इलेक्ट्रॉनिक बोली मंच पर तय हुई। यह कदम बेसल–3 मानकों के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने और दीर्घकालिक वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन बॉन्ड की आवंटन तिथि 20 मार्च 2026 तय की गई है, जबकि कॉल विकल्प 20 मार्च 2031 से उपलब्ध रहेगा और अंतिम परिपक्वता तिथि 20 मार्च 2036 निर्धारित है। निवेशकों की मजबूत प्रतिक्रिया से उच्च गुणवत्ता वाले बैंक ऋण साधनों में भरोसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

अनुपम मिश्रा ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद संभाला

अनुपम मिश्रा को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के बाद उनके नाम की सिफारिश की गई, जिसे भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में वे कोलकाता स्थित कंपनी मुख्यालय से संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण दायित्व से पहले अनुपम मिश्रा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित उर्वरक कंपनी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड में निदेशक (विपणन) के पद पर कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड में भी निदेशक (विपणन) के रूप में कार्य करते हुए खनिज आधारित उद्योगों के विपणन, निर्यात रणनीति और वैश्विक व्यापार विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में संस्थानों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया। तीन दशकों से अधिक के समृद्ध अनुभव के साथ अनुपम मिश्रा सार्वजनिक क्षेत्र के खनन और धातु उद्योग में एक अनुभवी प्रशासनिक एवं रणनीतिक नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। संसाधन प्रबंधन, परियोजना क्रियान्वयन और औद्योगिक विस्तार से जुड़े जटिल निर्णयों को समयबद्ध तरीके से लागू करने में उनकी विशेष दक्षता रही है। खनन क्षेत्र की व्यावसायिक रणनीतियों और वैश्विक बाजार की समझ उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में उनका प्रमुख लक्ष्य देश में तांबे के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, खनन गतिविधियों का आधुनिकीकरण करना तथा नई खदानों के अन्वेषण को गति देना है। उनके नेतृत्व में कंपनी आयात निर्भरता कम करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और दीर्घकालिक औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही संगठन की लाभप्रदता बढ़ाने, तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप तांबा क्षेत्र को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके नेतृत्व से कंपनी के भविष्य की विकास योजनाओं को नई दिशा मिलने की अपेक्षा की जा रही है।

प्रस्तुति
प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द की सोनम वांगचुक की हिरासत

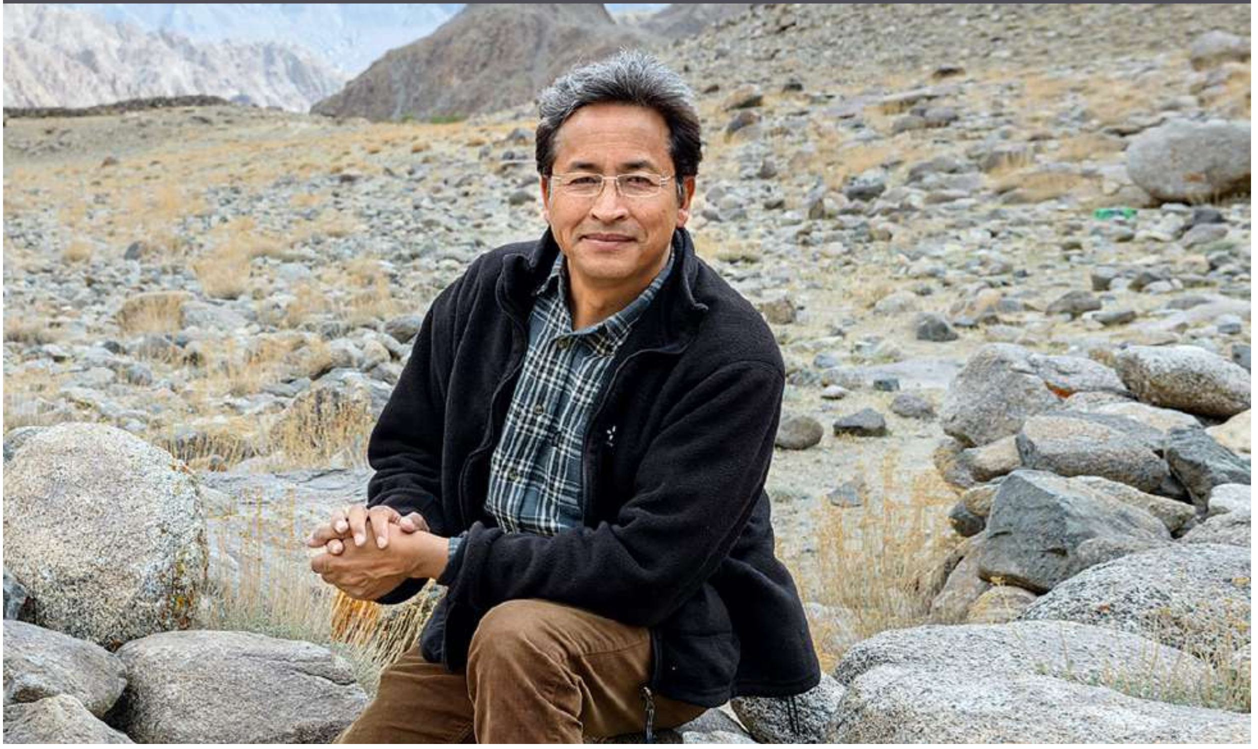

केंद्र सरकार ने लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिए गए शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा करने का फैसला किया है. सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उपलब्ध अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी है. वांगचुक को लद्दाख में हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन दिन बाद 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया था.वांगचुक एनएसए के तहत हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय व्यतीत कर चुके हैं. इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम बीते साल से अलग–अलग मौकों पर लद्दाख को संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आमरण अनशन और दिल्ली तक मार्च कर चुके हैं. बीते साल मार्च में उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे छठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 21 दिनों तक भूख हड़ताल की थी. वहीं अक्तूबर 2024 में ही इसी मांग को लेकर उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला था. हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर से उन्हें हिरासत में ले लिया था. साल 2025 में 35 दिन की उनकी भूख हड़ताल के 15वें दिन 24 सितंबर को लेह में आंदोलन हिंसक हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गयाी और तकरीबन 50 लोग घायल हुए थे. साल 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू–कश्मीर राज्य को दो अलग–अलग केंद्र शासित प्रदेशों.. जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. लद्दाख की अधिकतर जनता ने इस फैसले का स्वागत किया था क्योंकि जम्मू–कश्मीर से अलग होने की उनकी काफी पुरानी मांग थी. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, सरकार लद्दाख में विभिन्न हितधारकों और समाज के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके. इसमें कहा गया है, सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को सुगम बनाया जा सके. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए आंदोलन से सोनम वांगचुक चर्चा में रहे हैं लेकिन इससे पहले वह पहली बार थ्री इडियट्स फिल्म के बाद चर्चा में आए थे. यह दावा किया गया कि इस फिल्म का किरदार श्रेंचोश उनसे प्रेरित था. हालांकि उन्होंने इस बात को न्यूज वेबसाइट श्लल्लनटॉपश को दिए इंटरव्यू में खारिज किया था. इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाली थी

नौ साल की उम्र तक स्कूल नहीं गए

सोनम वांगचुक को एक शिक्षाविद, इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है. श्लल्लनटॉपश को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने लद्दाख के दूर–दराज के गांव से निकलकर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद

का सफर तय किया. 59 वर्षीय सोनम का जन्म साल 1966 में लेह के दुर्गम गांव उलेटोक्पो में हुआ था. वो बताते हैं कि उन्होंने नौ साल की उम्र तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी और इसी की वजह से वो कुछ अलग तरीके से सोच पाए. उनका कहना है कि स्कूल न जाने की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया और उन्होंने शुरुआती ज्ञान खुद के अनुभवों से हासिल किया.सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल राजनेता थे और नौ साल की उम्र के बाद सोनम वांगचुक को श्रीनगर के स्थानीय स्कूल में भेज दिया गया. इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने बताया था कि स्कूल में उन्हें अंग्रेजी की किताबें पकड़ा दी गईं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता था. उन्होंने बताया कि स्कूल के शिक्षक उन्हें पीछे की सीट पर बैठा देते थे या क्लास के बाहर खड़ा कर दिया करते थे. वो कहते हैं कि इस श्उत्पीड़नश से तंग आकर 12 साल की उम्र में वो लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अकेले बस से दिल्ली भाग आए. वो कहते हैं कि वहां पर बच्चों की बहुत भीड़ थी और उन्हें कई दिनों से कैंप में दाखिले का इंतजार करना पड़ रहा था.सोनम वांगचुक ये सब देखकर सीधे स्कूल में प्रिंसिपल के रूम में चले गए और उनसे दाखिला देने को कहा. प्रिंसिपल उनके इस जुझारूपन से खुश हुए और उन्हें दाखिला दे दिया. इसके बाद सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज (वर्तमान में एनआईटी) में लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने गए. सोनम वांगचुक कहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल ने जब उनके पिता का नाम देखा तो उनसे पूछा कि उनके पिता क्या करते हैं तो उन्होंने कहा कि वो पेशे से किसान हैं. हालांकि उस समय सोनम के पिता जम्मू–कश्मीर में मंत्री थे. सोनम का कहना था कि उन्होंने जब बीटेक का एक साल पूरा कर लिया तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे क्योंकि उनकी ऑप्टिक्स में दिलचस्पी थी. वहीं उनके पिता उन्हें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कह रहे थे. उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को चुना तो उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई का खर्चा देने से मना कर दिया जिसके बाद अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए कोचिंग की शुरुआत की. 19 साल की उम्र में उन्होंने एक होटल के कमरे को किराए पर लेकर जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो दो महीने में ही तीन साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस जुटा ली.

सेकमोल की शुरुआत और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सोनम वांगचुक कहते हैं कि यही वह मौका था जिसने उन्हें शिक्षा के लिए काम करने को प्रेरित किया. इसके बाद उन्होंने कॉलेज से निकलते ही साल 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल या सेकमोल) की शुरुआत की सेकमोल ने शुरुआत में कई सालों तक सरकारी स्कूल सिस्टम में बदलाव को लेकर काम किया. उसी के साथ ही सेकमोल के कैंपस में ऐसे अधिकतर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो स्कूली शिक्षा में फेल हो गए थे. सेकमोल में पारंपरिक स्कूली शिक्षा से हटकर पढ़ाई कराई जाती है जहां पर प्रकृति में रहकर और प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है. 1994 में

वांगचुक ने श्ऑपरेशन न्यू हॉपश (ओएनएच) की शुरुआत की. यह अब तक 700 शिक्षकों और 1000 ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग दे चुका.

इस दौरान लद्दाख में भी स्कूली शिक्षा में बदलाव देखा गया. जहां साल 1996 तक दसवीं कक्षा में सिर्फ पांच फीसदी बच्चे पास होते थे वो दर बढ़कर साल 2015 में 75 फीसदी हो गई. स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के मिशन को वांगचुक ने विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाना चाहा. इसी कोशिश के तहत तकरीबन सात साल पहले उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टर्नेटिव्स लद्दाख की शुरुआत की. उनका कहना है कि सेकमोल में किए गए शोध को हयाल में दूसरे स्तर पर ले जाया जाता है. वो बताते हैं कि सौर ऊर्जा से कमरों को गर्म करने का एक आविष्कार सेकमोल में शुरू किया गया था जिसे हयाल आगे लेकर गया. वांगचुक कहते हैं कि भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप में चीन से लगी सीमा पर सेना के कैंपों के लिए इस आविष्कार पर काम किया गया और इसे अफगानिस्तान में भी ले जाया गया है.साल 2018 में सोनम को शिक्षा के क्षेत्र में में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया

प्रस्तुति
प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

साए से बाहर - नीतीश की राजनीतिक धूप में कितना तप पाएंगे निशांत?

शक्ति प्रकाश
बिहार ब्यूरो प्रमुख

बिहार की राजनीति की तासीर हमेशा से ही अप्रत्याशित रही है। यहाँ की मिट्टी में समाजवाद की जड़ें जितनी गहरी हैं, सत्ता के समीकरण उतने ही उलझे हुए। हाल के दिनों में पटना की आबोहवा में एक नया नाम गूँज रहा हैकृ''निशांत कुमार''। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र, जो अब तक कैमरों की चमक और राजनीतिक नारों से कोसों दूर एक एकांत और आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे, अचानक बिहार की राजनीति के श्ध्रुवीय केंद्रश बन गए हैं। 8 मार्च को जनता दल (यूनाइटेड) में उनकी विधिवत एंट्री ने न केवल विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है, बल्कि जेडीयू के भीतर भी उत्तराधिकार की एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

इफ्तार की वह शाम और प्रतीकों की राजनीति

राजनीति में अक्सर शब्द वह नहीं कहते जो दृश्य कह जाते हैं। 19 मार्च की शाम, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित इफ्तार की दावत महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि निशांत कुमार के श्सॉफ्ट लॉन्चश का एक बड़ा मंच साबित हुई। शाम के करीब 6 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबी कैबिनेट सहयोगी विजय कुमार चौधरी के साथ पहुंचे। नीतीश ने वहां बमुश्किल कुछ मिनट बिताए और वापस चले गए। उनके जाने के ठीक एक मिनट के भीतर, सफेद रंग की स्कॉर्पियो में कड़ी सुरक्षा के बीच निशांत कुमार का प्रवेश हुआ। यह दृश्य प्रतीकात्मक था। नीतीश का जाना और निशांत का आनाकृमानो सत्ता के हस्तांतरण की कोई मूक पटकथा लिखी जा रही हो। उस शाम एक और दृश्य ने सबका ध्यान खींचा। निशांत की गाड़ी परिसर के अंदर तक गई थी, जिसके कारण बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय जैसे कद्दावर दिग्गजों को अपनी गाड़ियां बाहर छोड़कर पैदल चलकर आना पड़ा। जब सम्राट चौधरी इफ्तार स्थल पर पहुंचे, तो कुर्सियां कम पड़ गईं। उस समय निशांत, जो अब तक श्राजकुमारश की तरह सुरक्षा घेरे में थे, अचानक एक साधारण कार्यकर्ता की तरह उठे और अपनी कुर्सी सम्राट चौधरी को दे दी। वह खुद एक किनारे पड़ी काली प्लास्टिक की साधारण कुर्सी पर सहज भाव से बैठ गए। यह सादगी क्या स्वाभाविक थी या किसी सोची–समझी ब्रांडिंग का हिस्सा? यही वह सवाल है जो आज पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है।

निशांत कुमार संकोची बालक से मोस्ट वॉन्ग्ड कैरेक्टर तक

1980 में जन्मे निशांत कुमार का अब तक का जीवन किसी रहस्यमयी उपन्यास के पात्र जैसा रहा है। जहाँ लालू प्रसाद यादव के बेटे बचपन से ही राजनीति की एबीसीडी सीखते रहे, वहीं निशांत ने खुद को इस चमक–धमक से पूरी तरह काटकर रखा। नीतीश कुमार जब 1985 में पहली बार विधायक बने और

उन्हें पटना के बेली रोड पर सरकारी फ्लैट मिला, तब निशांत एक छोटे बच्चे थे। नीतीश कुमार के अभिन्न मित्र उदय कांत अपनी किताब 'श्नीतीश कुमार– अंतरंग दोस्तों की नजर मेंश' में लिखते हैं कि नीतीश अपने सिद्धांतों को लेकर इतने सख्त थे कि उन्होंने कभी परिवार को सत्ता के रसूख का अहसास नहीं होने दिया। निशांत की शुरुआती शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में हुई और फिर उन्हें मसूरी के मानव भारती स्कूल भेजा गया। हालांकि, मसूरी की वादियों में उनका मन नहीं लगा और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें पटना वापस बुला लिया गया, जहाँ उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। आरजेडी नेता जगतानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार, जो निशांत के बचपन के साथी रहे हैं, याद करते हैं कि निशांत हमेशा से अंतर्मुखी रहे हैं। वह कहते हैं, ष्नीतीश जी निशांत को बहुत नियंत्रण में रखते थे। उसके पास क्रिकेट किट तो थी, जिसके पीछे बच्चे लगे रहते थे, लेकिन वह खुद बहुत कम बोलता था। निशांत की यह चुप्पी ही आज उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए पहेली बनी हुई है। जो व्यक्ति दशकों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहा, वह अचानक बिहार जैसे जटिल राज्य की कमान कैसे संभालेगा?

नीतीश स्ट्रैटेजी परिवारवाद के आरोपों का काट

नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार रहा है श्परिवारवादश के खिलाफ उनका कड़ा रुख। उन्होंने बार–बार लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा है कि उनके लिए पूरा बिहार ही परिवार है। ऐसे में अपने बेटे को राजनीति में उतारना उनके लिए एक दोध ारी तलवार जैसा है। समाजशास्त्री और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्राध्यापक पुष्पेन्द्र का मानना है कि यहाँ नीतीश कुमार की एक बहुत ही सधी हुई रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी दिखती है। निशांत को सीधे तौर पर कोई बड़ा पद न देकर, उन्हें धीरे–धीरे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन निशांत ने जेडीयू की सदस्यता ली, उस समय नीतीश कुमार खुद पार्टी दफ्तर में मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि गांधी मैदान की ऐतिहासिक ईद की नमाज, जहाँ नीतीश हर साल जाते थे, इस बार उन्होंने खुद न जाकर निशांत को भेजा। यह नीतीश का एक ऐसा दांव है जिससे वह यह संदेश देना चाहते हैं कि निशांत उनकी इच्छा से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की मांग पर राजनीति में आए हैं। यह खुद को श्परिवारवादश के आरोपों से बचाने की एक नैतिक ढाल तैयार करने जैसा है।

माँ का प्रभाव और आध्यात्मिक झुकाव

निशांत कुमार के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनकी दिवंगत माता, मंजू कुमारी सिन्हा के प्रभाव को समझना अनिवार्य है। मंजू जी पेशे से शिक्षिका थीं और नीतीश कुमार की राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण निशांत का पालन–पोषण और वैचारिक निर्माण उन्हीं की देखरेख में हुआ। अशोक कुमार, जो जेडीयू कार्यालय में लंबे समय से कार्यरत हैं, भावुक होकर बताते हैं कि निशांत का अपनी माँ के प्रति जो लगाव था, वही उनकी सादगी और आध्यात्मिकता का मूल कारण है। अजीत कुमार एक पुरानी याद साझा करते हुए बताते हैं कि 2005 में उनकी शादी के समय मंजू आंटी ने निशांत से शादी करने को कहा था, लेकिन निशांत ने कभी इस ओर रुचि नहीं दिखाई। वह अक्सर ढीले–ढाले कुर्ते और स्लीपर्स में सार्वजनिक आयोजनों में चले जाते हैं। उनके संबोधन में आज भी श्पिता जीश और श्अंकलश जैसे शब्द होते हैं, जो उन्हें अन्य युवा नेताओं (जैसे तेजस्वी या चिराग) से अलग खड़ा करते हैं, जो अधिक पेशेवर और आक्रामक दिखते हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या सादगी ही काफी है?

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान

के प्रोफेसर जय देव का विश्लेषण थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि राजनीति सिर्फ सादगी का खेल नहीं है, यह श्परसेप्शनश यानी धारणा का खेल है। वह कहते हैं, षनिशांत को अभी अपनी बॉडी लैंग्वेज और वर्बल कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना होगा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव जैसे नेता अपने वोटरों से कनेक्ट करने के लिए एक खास तरह की ऊर्जा और दृढ़ता दिखाते हैं। इसके विपरीत, निशांत अभी भी एक आज्ञाकारी पुत्र की छवि में अधिक कैद दिखते हैं। नवीन पटनायक का उदाहरण देते हुए प्रोफेसर जय देव कहते हैं कि पटनायक भी शांत रहते हैं, लेकिन उनकी शांति में एक प्रशासनिक दृढ़ता दिखती है। निशांत को अगर बिहार का नेतृत्व करना है, तो उन्हें अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पॉलिटिकल आइडेंटिटी विकसित करनी होगी, जो उनके पिता के साये से इतर हो। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी चर्चित किताब 'श्अकेला आदमीश' में निशांत को श्एक विकट पहेलीश के रूप में चित्रित किया है। वह लिखते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भी अपने बेटे को समझना अक्सर एक चुनौती रहा है। संकर्षण के अनुसार, निशांत के भीतर एक तरह का अकेलापन और विरक्ति है। उन्होंने बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की, लेकिन वह सिर्फ एक डिग्री लेने जैसा था। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने कभी कॉरपोरेट जगत या प्रशासनिक सेवाओं की ओर रुख नहीं किया, बल्कि मुख्यमंत्री आवास (1, अणे मार्ग) के उस हिस्से में अपना समय बिताया जहाँ शांति हो। यह विरक्ति ही निशांत की सबसे बड़ी खूबी भी है और कमजोरी भी। खूबी इसलिए क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग का कोई दाग नहीं है। कमजोरी इसलिए क्योंकि राजनीति में श्विरक्तिश के लिए कोई जगह नहीं होतीय यहाँ चौबीसों घंटे सक्रियता और दांव–पेंच की जरूरत होती है।

टीम निशांत - जेडीयू के भीतर एक नया शक्ति केंद्र

भले ही निशांत कुमार खुद को लो–प्रोफाइल रख रहे हों, लेकिन जेडीयू के भीतर एक श्टीम निशांतश का जन्म हो चुका है। पार्टी के नौजवान विधायक, जो भविष्य में अपनी सीट सुरक्षित रखना चाहते हैं, अब निशांत की ओर देख रहे हैं। इस्लामपुर से विधायक रूहैल रंजन, जो निशांत के बीआईटी मेसरा के सहपाठी भी रहे हैं, इस टीम के प्रमुख सदस्य हैं। रूहैल रंजन का दावा है कि निशांत कोई श्इंट्रोवर्टश नहीं हैं, बल्कि वह एक संवेदनशील और शिक्षित विचारक हैं। वह कहते हैं, षबख्तियारपुर में हाल ही में जब निशांत गए थे, तो वहां 20 हजार लोगों का स्वतः स्फूर्त आना इस बात का सबूत है कि बिहार की जनता एक नया और साफ–सुथरा चेहरा चाहती है।ष पार्टी के भीतर यह ध ारणा प्रबल हो रही है कि नीतीश के बाद अगर कोई जेडीयू को एकजुट रख सकता है, तो वह केवल निशांत ही हैं, क्योंकि किसी अन्य नेता के नाम पर पार्टी में बगावत हो सकती है।

विरासत की चुनौती और समाजवाद का भविष्य

क्या निशांत, नीतीश की विरासत को संभाल पाएंगे? यह सवाल जितना सीध ा है, इसका जवाब उतना ही जटिल। नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में बिहार में जो श्सोशल इंजीनियरिंगश की है, वह जातियों के एक बारीक संतुलन पर आधारित है। उन्होंने महादलितों, अति पिछड़ों और महिलाओं का एक ऐसा साइलेंट वोट बैंक बनाया जिसने लालू यादव के माय समीकरण को ध्वस्त कर दिया। अजीत कुमार जैसे पुराने साथी संशय में हैं। वह कहते हैं कि निशांत

को राजनीति की बुनियादी समझ तो है, लेकिन क्या उनके पास वह किलर इंस्टिंक्ट है जो नीतीश कुमार में था? नीतीश ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार पलटी मारी, कई गठबंधन तोड़े और जोड़े, लेकिन हमेशा सत्ता के केंद्र में बने रहे। क्या निशांत जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीति के इस कीचड़ में कमल की तरह खिल पाएगा या फिर वह इस व्यवस्था में दब जाएगा? इसके अलावा, समाजवाद का भविष्य भी दांव पर है। जेडीयू और आरजेडी दोनों समाजवाद की वैचारिक जमीन से उपजी पार्टियां हैं। समाजशास्त्री पुष्पेन्द्र का मानना है कि बिहार में उस समाजवाद की धारा का अब अवसान काल (अंत का समय) चल रहा है जो 60 के दशक में शुरू हुआ था। तेजस्वी यादव या निशांत कुमार जैसे नए चेहरे उस वैचारिक गहराई के साथ नहीं आते जो लोहिया या जयप्रकाश नारायण के समय में थी। निशांत के लिए चुनौती सिर्फ मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बल्कि उस वैचारिक जमीन को बचाना है जिस पर जेडीयू खड़ी है।

भविष्य का खाका-सुपर सीएम और नई सत्ता संरचना

बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा यह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद क्या होगा। अप्रैल 2026 के आसपास उनके पद छोड़ने की चर्चा जोरों पर है। क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा? लोजपा (आर) के प्रमुख चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति बन चुकी है। सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने कई मंचों से सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा है कि ष्अब आगे यही देखेंगे। लेकिन असली पेच जेडीयू के भीतर है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, तो जेडीयू का वजूद खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में जेडीयू के विधायक चाहते हैं कि कम से कम डिप्टी सीएम या पार्टी अध्यक्ष के तौर पर निशांत कुमार का नाम आगे किया जाए ताकि नीतीश का प्रभाव बना रहे। विधायक रूहैल रंजन का एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है सीएम कोई भी बने, सुपर सीएम नीतीश जी ही रहेंगे। यह इशारा है कि निशांत कुमार को सत्ता के औपचारिक ढांचे में फिट किया जाएगा, जबकि रिमोट कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगा। निशांत कुमार के पास अपने पिता की विरासत में मिली क्लीन इमेज है, लेकिन उनके पास प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक आक्रामकता का अभाव है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ जाति, धर्म और अपराध की त्रिवेणी राजनीति की दिशा तय करती है, वहां निशांत की सादगी कितनी सफल होगी, यह वक्त बताएगा। निशांत कुमार फिलहाल एक प्रयोग हैं जेडीयू का वह प्रयोग जो पार्टी को परिवारवाद के दाग से बचाते हुए एक उत्तराधिकारी देना चाहता है। यदि वह सफल होते हैं, तो यह भारतीय राजनीति में एक नई तरह की सात्विक राजनीति की शुरुआत होगी। और यदि वह असफल होते हैं, तो जेडीयू के लिए नीतीश कुमार के बाद अपना अस्तित्व बचा पाना मुश्किल होगा। निशांत अब मौन तोड़ चुके हैं। वह कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। उनके चेहरे पर दिखने वाला संकोच धीरे–धीरे आत्मविश्वास में बदल रहा है। लेकिन बिहार की कंटीली जमीन पर उनके पैर कितने मजबूत पड़ते हैं, यह 2026 के सियासी बदलावों के साथ साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है, अब गेंद निशांत और बिहार की जनता के पाले में है।

'नक्सलवाद लगभग खत्म' क्या सच में अपने अंत की ओर है भारत का सबसे लंबा आंतरिक संघर्ष?

इंजीनियर ए पी सिंह
राजनीतिक संपादक

लोकसभा में 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा कियाकृभारत अब लगभग नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। उनके अनुसार जिन इलाकों को कभी माओवादी प्रभाव का "कोर जोन" माना जाता था, वहां अब प्रशासन की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, स्कूल खुल रहे हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक लोगों की पहुंच बन रही है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नक्सलवाद की जड़ केवल गरीबी या विकास की कमी नहीं, बल्कि एक वैचारिक संघर्ष रहा है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य तय किया था, वह लगभग हासिल कर लिया गया है। यह बयान सिर्फ एक प्रशासनिक उपलब्धि का दावा नहीं था। यह भारत के सबसे लंबे चले आ रहे आंतरिक सुरक्षा संघर्षों में से एक के संभावित अंत की घोषणा जैसा था। लेकिन संसद के भीतर और बाहरकृ दोनों जगह इस दावे को लेकर सवाल उठने लगे।

संसद में टकराए दावे और सवाल

गृह मंत्री के बयान के अगले ही दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक सरकार का अभियान नहीं रही है और इसे राजनीतिक श्रेय के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में यह कहना कि पिछली सरकारों ने इस लड़ाई का समर्थन नहीं किया, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। लोकसभा में चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सरकार से एक बुनियादी सवाल पूछा "अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो फिर बस्तर जैसे इलाकों में इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों बनी हुई है?" यह सवाल दरअसल उस जमीनी सच्चाई की ओर इशारा करता है, जहां सुरक्षा अभियानों की सफलता और स्थायी शांतिकृदोनों को अलग–अलग मानकों से देखा जाता है।

2024 के बाद क्यों तेज हुई कार्रवाई?

अगस्त 2024 में जब केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 की समय सीमा तय की, उसके बाद माओवादी प्रभावित इलाकों में सुरक्षा अभियानों की गति अचानक तेज हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के अनुसार इस दौरान रणनीति में कई स्तरों पर बदलाव किए गए। सुरक्षाबलों को अधिक परिचालन स्वतंत्रता दी गई। जंगलों के भीतर स्थानीय सूचना तंत्र को मजबूत किया गया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जैसी स्थानीय इकाइयों का अधिक उपयोग हुआ। ड्रोन और तकनीकी निगरानी का इस्तेमाल बढ़ा। इन प्रयासों का असर भी दिखाई दिया। पिछले दो वर्षों में राज्य में 531 माओवादी मारे गए, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं और हजारों कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। संगठन की शीर्ष नेतृत्व संरचना को लगातार झटके लगे। मई 2025 में सीपीआई (माओवादी) के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू की

मुठभेड़ में मौत को इस अभियान का निर्णायक मोड़ माना गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव और वरिष्ठ नेता वासुदेव राव ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 2025 में केंद्रीय समिति सदस्य माडवी हिडमा की मुठभेड़ में मौत और फरवरी 2026 में संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी के सरेंडर ने संगठन की सैन्य संरचना को और कमजोर कर दिया।

बस्तर: जहां से तय होती थी रणनीति

भारत में नक्सल आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के छं•सइंतप से हुई थी। धीरे–धीरे यह आंदोलन बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तक फैल गया। वर्ष 2004 में कई संगठनों के विलय के बाद Communist Party of India (Maoist) का गठन हुआ और आंदोलन को केंद्रीकृत नेतृत्व मिला। समय के साथ छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इस आंदोलन का सबसे मजबूत आधार बन गया। घने जंगल, सीमित सड़क संपर्क, प्रशासन की कमजोर मौजूदगी और स्थानीय असंतोषकृइन सबने मिलकर इस क्षेत्र को दशकों तक माओवादी गतिविधियों का केंद्र बनाए रखा। दंडकारण्य क्षेत्र में माओवादियों ने समानांतर ढांचा विकसित कर लिया था, जिसमें जन अदालतें, हथियारबंद दस्ते और स्थानीय नेटवर्क शामिल थे। एक समय 'रेड कॉरिडोर' 12 राज्यों तक फैला हुआ था और करोड़ों लोग इसके प्रभाव क्षेत्र में आते थे।

क्या नेतृत्व खत्म होने से आंदोलन खत्म हो जाता है?

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पिछले दो वर्षों में सबसे बड़ा असर माओवादी संगठन की नेतृत्व संरचना पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के अनुसार राज्य में सक्रिय माओवादी कैडरों की संख्या अब बेहद सीमित रह गई है और वे किसी बड़े हमले की स्थिति में नहीं हैं। इसी तरह नक्सल ऑपरेशन्स से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठन की सैन्य संरचना लगभग टूट चुकी है और जो कैडर बचे हैं, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है। लेकिन इतिहास बताता है कि किसी भी वैचारिक आंदोलन का भविष्य सिर्फ नेतृत्व के आधार पर तय नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा कि 2014 के बाद सरकार की रणनीति में बड़ा बदलाव आया। सुरक्षा कार्रवाई के साथ–साथ प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी जोर दिया गया।

इस दौरान

–596 नए पुलिस स्टेशन बनाए गए

–सैकड़ों नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए

–ड्रोन और सैटेलाइट आधारित निगरानी बढ़ाई गई

–विकास के मोर्चे पर 17,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को मंजूरी मिली

–लगभग 12,000 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हुआ

–करीब 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए

–बैंक शाखाएं, एटीएम और पोस्ट ऑफिस खोले गए

सरकार का मानना है कि इन कदमों ने माओवादी नेटवर्क की पकड़ कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई।

आत्मसमर्पण: सफलता की कहानी या नई चुनौती?

पिछले कुछ वर्षों में हजारों माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आवास जैसी योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर काम कर रहे पत्रकारों का

कहना है कि असली चुनौती अब शुरू होती है। बस्तर क्षेत्र में लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार विकास तिवारी के अनुसार माओवादी ढांचे के कमजोर पड़ने से एक नया सामाजिक "वैक्यूम" पैदा हुआ है। उनके मुताबिक सवाल यह नहीं है कि माओवादी कमजोर हुए या नहीं बल्कि यह है कि उनकी जगह कौन लेगा। आत्मसमर्पण कर चुके कैडरों के सामने सिर्फ आर्थिक पुनर्वास ही चुनौती नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता भी एक बड़ा सवाल है। जिन इलाकों में दशकों तक हिंसा का असर रहा है, वहां स्थानीय समुदायों के लिए इन लोगों को स्वीकार करना आसान नहीं होता। यदि स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ता है, तो यह प्रशासन के लिए एक नई चुनौती बन सकता है।

जमीन, जंगल और भविष्य की चिंता

बस्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सड़क, स्कूल, अस्पताल और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं लंबे समय से प्राथमिक मांग रही हैं। अब इन सुविधाओं की पहुंच बढ़ रही है।

लेकिन इसके साथ एक नई चिंता भी सामने आई है

खनन परियोजनाएं, चौड़ी सड़कें और बड़े निवेश इन सबको लेकर कई आदिवासी समुदायों के मन में आशंकाएं हैं कि विकास की तेज रफ्तार कहीं उनके पारंपरिक जीवन और संसाधनों पर असर न डाल दे। स्थानीय स्तर पर यह डर भी सामने आता है कि माओवादी प्रभाव कम होने के बाद बाहरी हस्तक्षेप बढ़ सकता है।

क्या खतरा पूरी तरह खत्म हो गया है?

सुरक्षा एजेंसियों के सामने अभी भी कुछ व्यावहारिक चुनौतियां मौजूद हैं। जंगलों में पहले से लगाए गए आईईडी, छोटे बचे हुए कैडर समूह और पुराने नेटवर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इन समूहों के दोबारा संगठित होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिन इलाकों में राज्य की मौजूदगी हाल ही में बनी है, वहां भरोसा कैसे कायम किया जाएगा।

क्या यह अंत है या एक नए दौर की शुरुआत?

पिछले दो वर्षों में सुरक्षा अभियानों ने माओवादी संगठन की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर जरूर किया है। लेकिन किसी भी लंबे सामाजिक राजनीतिक संघर्ष का अंत सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई से तय नहीं होता। असली परीक्षा अब शुरू होती है क्या प्रशासनिक पहुंच भरोसे में बदलेगी? क्या विकास स्थानीय आकांक्षाओं के साथ संतुलन बना पाएगा? और क्या बस्तर जैसे इलाकों में शांति स्थायी रूप ले पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब तय करेंगे कि नक्सलवाद का यह अध्याय वास्तव में समाप्त हुआ है या यह सिर्फ एक नए चरण की शुरुआत है।

छह नेताओं की वापसी से कांग्रेस मजबूत, हरीश रावत को लेकर मतभेद उजागर

सुनील नेगी
उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं बसपा और भाजपा के छह पूर्व विधायकों और नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस का मनोबल ऊंचा हुआ है और भाजपा का मनोबल गिरा है। हालांकि, कांग्रेस में आंतरिक कलह अभी भी जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कथित तौर पर विवादों में घिरे हैं। हाल ही में आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक में हरीश रावत अकबर रोड स्थित 24 कार्यालय में अनुपस्थित रहे, जबकि उन्होंने पहले ही 15 दिनों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी थी। यह बैठक उन छह विधायकों के पार्टी में शामिल होने के दिन हुई थी। इतना ही नहीं, उनके खास साथियों और पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह कुंजवाल ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए खुलेआम कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस हाई कमांड और केंद्रीय हाई कमांड द्वारा हरीश रावत का जिस तरह से अपमान किया गया और राम नगर से कांग्रेस के बागी नेता और निर्दलीय उम्मीदवार संजय नेगी को स्वीकार नहीं किया गया, उससे साफ है कि उन्हें नजर अंदाज और दरकिनार किया जा रहा है, जिससे उनके राजनीतिक अनुभव, प्रभाव और प्रतिष्ठा को कम आंका जा रहा है। कुंजवाल ने कांग्रेस हाई कमांड को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री को नजरअंदाज किया जाता है, तो कांग्रेस राज्य में सत्ता में वापस नहीं आ सकती। नाम न छापने की शर्त पर भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हरीश रावत के करीबी और दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा सार्वजनिक रूप से दिया गया यह स्पष्ट बयान विद्रोह का साफ संकेत देता है। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं और हाई कमांड को भी कुंजवाल के रवैये और बयान में विद्रोह की झलक दिख रही है, हालांकि उन्होंने इस बात पर भरोसा जताया है कि रावत कहीं नहीं जा रहे हैं, जबकि उनकी वफादारी बदलने की अफवाहें चल रही हैं। ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि उनके करीबी लोग उन्हें भगवा पार्टी में शामिल होने की सलाह दे रहे हैं और ऐसी अफवाहें हैं कि अगर रावत इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें कोई बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, हालांकि विपक्षी खेमे के कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि रावत कभी ऐसा रुख नहीं अपनाएंगे। दूसरी ओर, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत ने भी मीडिया से बात करते हुए रावत के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह नहीं समझना चाहिए कि वे पार्टी के एकमात्र नेता हैं और उनके बिना कांग्रेस राज्य में वापसी नहीं कर सकती। उनका तीखा जवाब हरीश रावत की ओर था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आज पूरी कांग्रेस एक ही पक्ष में खड़ी नजर आ रही है और हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में पूरी तरह से हाशिए पर चले गए हैं। इस बीच, हरीश रावत ने कुंजवाल की बात को फिर से पूरी तरह से समर्थन देने की कोशिश की है और पार्टी में अपनी उपेक्षा पर परोक्ष रूप से नाराजगी जताते हुए युवा पीढ़ी को आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे उनका आशीर्वाद और समर्थन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे दादीची की तरह ही उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने इस संबंध में कुंजवाल की फेसबुक टाइमलाइन पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिससे यह आभास होता है कि रावत को दरकिनार किए जाने के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और 2027 में चुनाव लड़ने वाले युवा उम्मीदवारों को हर तरह से अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देने का आश्वासन दिया है। उनका लंबा पोस्ट हिंदी में इस प्रकार हैरू 59 वर्षों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद, यह मेरा स्वाभाविक अधिकार है कि मैं कुछ समय के लिए छुट्टी लूं। इस लंबे अटूट कार्यकाल के दौरान, ऐसे क्षण आ सकते हैं जब आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो। परिस्थितियों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी इस अर्जित अवकाश पर कोई आपत्ति न की जाए। श्री गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ मेरा गहरा भावनात्मक संबंध है और उनके शब्द स्वाभाविक हैं। हो सकता है कुछ लोग मुझे भाई या पिता तुल्य मानते हों और उनकी भी कुछ भावनाएँ हों, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने अथक 59 वर्षों के दौरान, मैंने हमेशा यह याद रखा है कि मैं एक पार्टी कार्यकर्ता हूँ और मैंने हमेशा पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के अंतिम निर्णय को स्वीकार किया है। हो सकता है मैंने कभी–कभी थोड़ी विनती की हो, लेकिन अंततः मैंने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार किया है। यह लंबी प्रतिज्ञा, जिसने अब एक संकल्प का रूप ले लिया है, न तो तोड़ी जाएगी और न ही बदली जाएगी। 2027 में अपने लिए संभावनाएं देखने वाले युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि दधीचि की तरह, अगर उन्हें मेरी हड्डियों की जरूरत पड़े, तो हरीश रावत की हड्डियां उनके भविष्य को संवारने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी। अवकाश के दौरान भी मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ और जी तोड़ मेहनत करता हूँ। इस लंबे समय में मेरा कई लोगों, समूहों, क्षेत्रों, मान्यताओं और जनमानस की अपेक्षाओं से संपर्क हुआ है। जीवन के इस मोड़ पर मुझे उनकी सलाह की आवश्यकता है और उनसे संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता महसूस होती है। रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जो आलोचक मेरे बारे में जानने को उत्सुक हैं, मैं उनका आभारी हूँ।

भावनाओं के अनंत आकाश में चमकता मेरा चांद आसमां में - 'अमर जैन

राजीव कुमार ओझा
लेखक एवं पत्रकार

शिक्षिका वत्सला सिंह अक्स का सद्यः प्रकाशित काव्य संकलन हिन्दी दैनिक देश पथ लखनऊ के सलाहकार संपादक –पुस्तक समीक्षक राजीव कुमार ओझा के कुशल संपादन में सजी कृति – मेरा चांद आसमां में समकालीन हिंदी काव्य जगत में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। यह संकलन

पुस्तक समीक्षा

कृति मेरा चांद आसमां में
काव्य संकलन
लेखिका -वत्सला सिंह अक्स
संपादक- राजीव कुमार ओझा
भूमिका - डा.शाहिद अली
प्रोफेसर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ
आवरण पृष्ठ शिल्पी -विकास चौधरी
प्रकाशक-हिन्दी श्री पब्लिकेशन

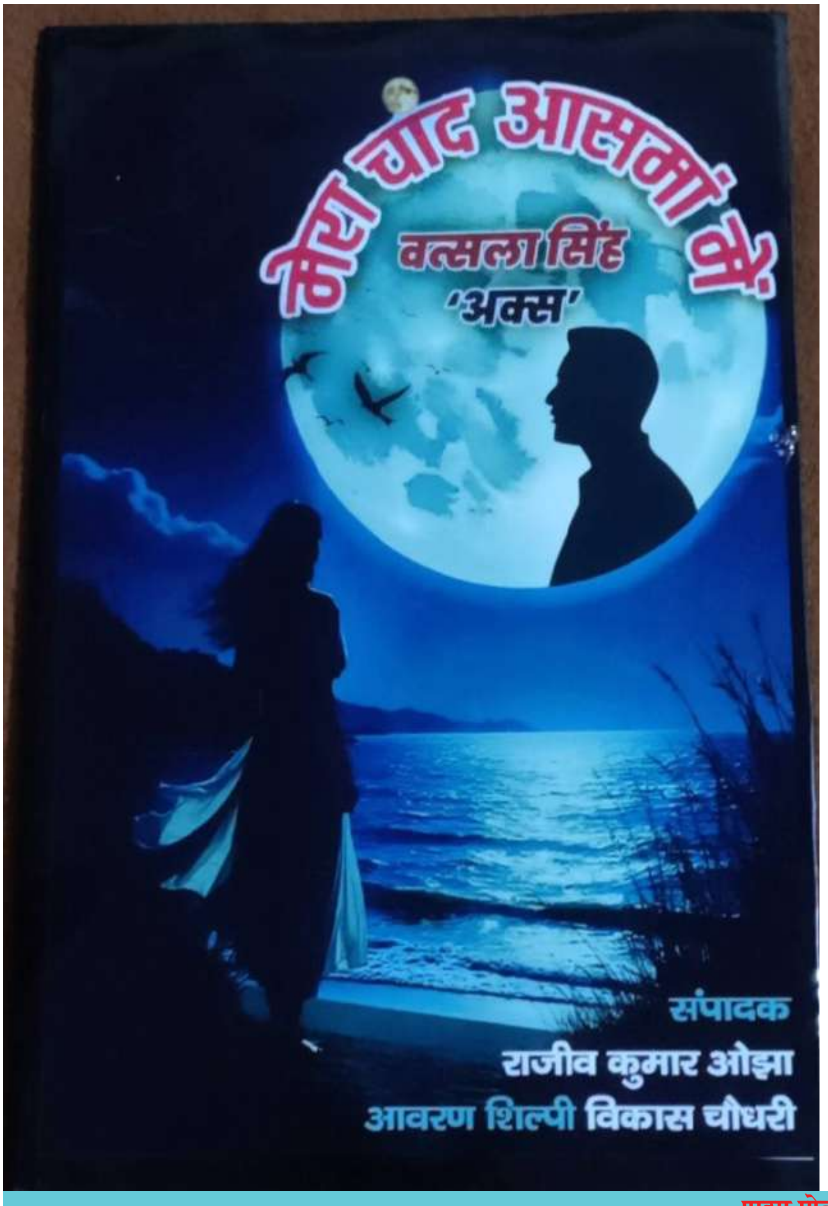

केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि विविध मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, नारी मन के भावों, पुरुषवादी मानसिकता से जूझती नारी की व्यथा, स्त्री पर थोपी गई रुढ़िवादी सामाजिक बंदिशों,भ्रष्ट व्यवस्था की कुनीतियों, पर्यावरण पर गहराते संकट,सामाजिक सरोकारों को रेखांकित करती कविताओं का एक सुंदर इंद्रधनुषी कोलाज है। सुंदर,सहज, सरस, बोधगम्य ,सुग्राह्य भाषा शैली में सृजित इस काव्य संकलन की हर रचना पाठक पर कवयित्री के वैदुष्य की अमिट छाप छोड़ती है। कहीं कवयित्री वत्सला सिंह अक्स का शिक्षक का किरदार समाज के समक्ष खड़ी चुनौतियों से हमें आगाह करता है तो कहीं स्त्री को भोग्या समझने की कुंठित पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ एक विद्रोही नारी के किरदार में कवयित्री पुरुषवादी मानसिकता से प्रताड़ित नारी में जूझने की ऊर्जा का संचार करती हैं। इस काव्य संकलन की सबसे बड़ी शक्ति इसकी विविधता है। इसमें जहां एक ओर प्रेम की कोमलता है, वहीं दूसरी ओर जीवन के संघर्षों की प्रखर अभिव्यक्ति भी है। संपादक के रूप में राजीव कुमार ओझा जी ने विभिन्न रचनाओं के भावों को एक सूत्र में पिरोने का सराहनीय कार्य किया है। कविताओं का चयन और उनका क्रम पाठक को बांधे रखता है। संकलन की भाषा सरल, सुबोध और मर्मस्पर्शी है, जो सीधे पाठक के हृदय तक उतरती है। यह काव्य संकलन उन सभी पाठकों के लिए एक अनमोल उपहार है जो शब्दों में भावनाओं की तलाश करते हैं। विदुषी कवयित्री वत्सला सिंह अक्स का यह प्रयास हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। जब शब्द संवेदना की स्याही में डूबते हैं, तभी ''मेरा चांद आसमां'' में जैसी कृतियां जन्म लेती हैं।

नया 'धर्म स्वतंत्रता कानून 2026' क्या बदला, और क्यों उठ रहे सवाल?

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के आधार पर कराए जाने वाले ध र्मांतरण पर रोक लगाना है। सरकार के मुताबिक, नए कानून में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कुछ मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा भी शामिल की गई है। हालांकि, इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने गंभीर आपत्तियाँ दर्ज की हैं। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का कहना है कि यह कानून केवल जबरन धर्मांतरण रोकने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे व्यक्तिगत आस्था से जुड़े मामलों में डर और निगरानी का माहौल बन सकता है। उनका यह भी कहना है कि राज्य में पहले से ही ऐसा कानून मौजूद है, इसलिए नए प्रावधानों की आवश्यकता और उनके संभावित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के अलग–अलग इलाकों से चर्चों पर हमलों, ईसाई आदिवासियों के साथ हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और अंतिम संस्कार से जुड़े विवादों की खबरें सामने आती रही हैं। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों की सक्रियता भी बढ़ी है, जो आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर अपनी अलग दृष्टि रखते हैं।

नए कानून में क्या हैं प्रमुख बदलाव?

राज्य सरकार के अनुसार, यह विधेयक 1968 के उस कानून की जगह लेगा जिसे राज्य गठन के बाद मध्य प्रदेश से अपनाया गया था। नए कानून में ध र्मांतरण की परिभाषा का विस्तार करते हुए डिजिटल माध्यमों और आर्थिक प्रलोभनों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। विधेयक के अनुसार ''धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित व्यक्ति और प्रक्रिया से जुड़े धार्मिक प्रतिनिधि को प्रशासन को पूर्व सूचना देनी होगी इस सूचना को सार्वजनिक किया जाएगा 30 दिनों की अवधि में इस पर आपत्तियाँ दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके अलावा, धर्म परिवर्तन कराने वाले पुजारी, मौलवी या अन्य धार्मिक प्रतिनिधि को भी प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। नए कानून के तहत धर्मांतरण से जुड़े सभी अपराध ''गैर–जमानती'' होंगे। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि प्रक्रिया में किसी तरह का दबाव, प्रलोभन या धोखाधड़ी शामिल नहीं थी।

–अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 वर्ष तक की सजा

–महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति–जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मामलों में 10 से 20 वर्ष तक की सजा

–सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास तक का प्रावधान

सरकार का कहना है कि यह कानून

जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए आवश्यक है, जबकि विपक्ष का तर्क है कि इससे व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

पहले से लागू कानून और अन्य राज्यों का अनुभव

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए पहले से 1968 का कानून लागू था, जिसे राज्य गठन के बाद अपनाया गया था। सरकार का कहना है कि नया कानून उसी ढांचे को मजबूत करता है, जबकि आलोचक इसे अनावश्यक विस्तार मानते हैं। अन्य राज्यों के अनुभव भी इस बहस को महत्वपूर्ण बनाते हैं। मध्य प्रदेश में 2020 के अध्यादेश और 2021 के कानून के बाद अगस्त 2025 में विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 283 मामले दर्ज हुए। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत मामले अदालतों में लंबित थे। शेष मामलों में 50 अभियुक्त बरी हुए और केवल सात मामलों में सजा हो सकी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कानूनों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आपराधिक कानून का उपयोग निर्दोष नागरिकों को परेशान करने के औजार के रूप में नहीं होना चाहिए।

ऐतिहासिक संदर्भ : धर्मांतरण नियंत्रण के पुराने प्रयास

छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयास नए नहीं हैं। ऐतिहासिक रूप से भी ऐसे कानून मौजूद रहे हैं। 1936 में रायगढ़ रियासत के कन्वर्जन एक्ट के तहत धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को पहले अदालत में आवेदन देना अनिवार्य था। इसी तरह 1945 में सरगुजा रियासत के अपोस्टेसी एक्ट में धर्म परिवर्तन से तीन महीने पहले सरकार को सूचना देना आवश्यक था। बिना अनुमति धर्म परिवर्तन अवैध माना जाता था।

क्या यह कानून अल्पसंख्यकों को प्रभावित करेगा?

बस्तर में वकालत करने वाले अधिवक्ता डिग्री प्रसाद चौहान का कहना है कि यह एक "टारगेटेड कानून" साबित हो सकता है और इसका असर खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर ईसाइयों और मुसलमानों पर पड़ सकता है। उनके अनुसार, ऐसे कानून नागरिकों की संवैधानिक स्वतंत्रता से टकराव पैदा करते हैं। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर भी इस आशंका से सहमत दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि आदिवासी पारंपरिक रूप से प्रकृति–पूजक हैं और उन्हें किसी एक धार्मिक पहचान में बांधना उचित नहीं है। संविधान सभी नागरिकों को अपनी आस्था चुनने का अधिकार देता है।

वरिष्ठ पत्रकार विकास तिवारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ खासकर बस्तर क्षेत्र में माओवाद के बाद धर्मांतरण और उससे जुड़े सामाजिक तनाव एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं।

ईसाई संगठनों की चिंता और सरकार का पक्ष

राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि यह कानून राज्य में बढ़ते सामुदायिक तनाव और विवादों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं, नाबालिगों, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों को विशेष रूप से गंभीर श्रेणी में रखा गया है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका ऐसे मामलों में पाई जाती है, तो उसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है। दूसरी ओर, ईसाई संगठनों ने इस कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। ईसाइयों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार, 2025 में जनवरी से नवंबर के बीच देशभर में ईसाई समुदाय के खिलाफ 700 से अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें लगभग 48 प्रतिशत मामले केवल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सामने आए। फोरम के अनुसार, 2025 में छत्तीसगढ़ में ईसाई समुदाय के अंतिम संस्कार से जुड़े 19 विवाद सामने आए, जबकि 2024 में ऐसे लगभग 30 मामले दर्ज किए गए थे। कांकेर जिले की एक घटना और बस्तर के एक धर्मांतरित आदिवासी ईसाई सुभाष बघेल के अंतिम संस्कार से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फोरम के राष्ट्रीय समन्वयक ए.सी. माइकल का कहना है कि यदि सरकार जबरन धर्मांतरण के ठोस आंकड़े पेश नहीं कर पा रही है, तो ऐसे कानून की आवश्यकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनके अनुसार, स्वेच्छा से धर्म चुनने के अधिकार पर कानूनी प्रतिबंध संवैधानिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रस्तुति
प्राइम स्पेक्टेटर डेस्क

नमाजियों के लिए जगह कम पड़ी तो हिंदू परिवार के पाँच भाइयों ने ईदगाह के लिए दान कर दी जमीन

रानू पाठक
राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

राजस्थान के सीकर जिले का गुहाला गांव इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है। करीब सात हजार की आबादी वाले इस गांव में एक हिंदू परिवार के पाँच भाइयों ने ईदगाह के विस्तार के लिए अपनी कृषि भूमि का एक हिस्सा दान कर दिया। स्थानीय लोग इसे गांव के लंबे समय से चले आ रहे आपसी भरोसे और भाईचारे की परंपरा का उदाहरण मान रहे हैं। उदयपुरवाटी जाने वाली मुख्य सड़क पर बसे इस गांव का इतिहास उसकी पुरानी हवेलियों और पारंपरिक बसावट में झलकता है। गांव के भीतर से गौशाला होते हुए सांवाली ढाणी की ओर जाने वाले रास्ते के पास ही भोपाल राम सैनी और उनके भाइयों के घर हैं। उनके खेतों के आखिरी छोर पर स्थित ईदगाह से सटी जमीन का हिस्सा उन्होंने नमाजियों की सुविधा के लिए दान किया है।

छोटी पड़ रही थी ईदगाह

गुहाला और आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हर साल ईद की नमाज पढ़ने के लिए इसी ईदगाह में आते हैं। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक ईदगाह काफी पुरानी है, लेकिन समय के साथ नमाजियों की संख्या बढ़ने लगी और जगह कम पड़ने लगी। करीब 65 वर्षीय हाजी मोहम्मद तौफीक बताते हैं कि ईद के दिन इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोगों को खड़े होने की जगह भी मुश्किल से मिलती थी। आसपास के कई गांवों में ईदगाह नहीं होने की वजह से लोग यहां आते हैं। इसी समस्या को देखते हुए समुदाय के लोगों ने सैनी परिवार से जमीन देने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। ईद के मौके पर नमाज के बाद गांव में इन भाइयों का सम्मान भी किया गया। इस पहल का वीडियो सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में भी इसकी चर्चा होने लगी।

जमीन के बदले पैसे लेने से किया इनकार

ईदगाह से सटे खेत सैनी परिवार के पाँच भाइयों के हैं। परिवार के सदस्य पूरणमल सैनी बताते हैं कि जब उनसे ईदगाह के लिए जमीन देने की बात कही गई तो उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। उनके अनुसार, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमीन के बदले पैसे देने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने इसे आपसी सम्मान और रिश्तों का मामला मानते हुए स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ जमीन दी, बल्कि ईदगाह की बाउंड्री बनवाने के काम में भी सहयोग किया। भोपाल राम सैनी भी इस फैसले को सहज मानते हैं। उनका कहना है कि जब नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जगह कम पड़ रही थी, तो जमीन देना स्वाभाविक लगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो वे और जमीन देने पर भी विचार कर सकते हैं।

फैसले को लेकर कुछ लोगों ने जताई आपत्ति

हालांकि इस कदम की व्यापक सराहना हुई, लेकिन कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। पूरणमल सैनी बताते हैं कि कुछ रिश्तेदारों और परिचितों ने फोन करके पूछा कि मुस्लिम समुदाय को जमीन क्यों दी गई। इस पर उनका जवाब था कि अगर किसी हिंदू मंदिर के लिए भी जमीन मांगी जाएगी, तो वे उसी तरह सहयोग करेंगे। उनके अनुसार यह फैसला किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गांव में लंबे समय से चले आ रहे आपसी विश्वास और संबंधों के आधार पर लिया गया। वे कहते हैं कि उनका परिवार खेती और मजदूरी से जुड़ा है और गांव में सभी लोग वर्षों से आपसी सहयोग के साथ रहते आए हैं।

गांव की सामाजिक बनावट भी है अहम

गुहाला गांव की सामाजिक संरचना इस घटना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां विभिन्न समुदायों के लोग साथ रहते हैं। अनुमानित तौर पर गांव की आबादी में करीब 25 प्रतिशत मुस्लिम, लगभग इतनी ही अनुसूचित जाति और करीब उतनी ही सैनी समुदाय के लोग हैं, जबकि बाकी अन्य समुदायों से आते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 1990 से पहले गुहाला गांव क्षेत्र की एक बड़ी पंचायत हुआ करता था। बाद में परिसीमन के बाद आसपास के कई गांव अलग पंचायतों में शामिल हो गए। यह गांव कभी गुड़ की बड़ी मंडी के रूप में भी जाना जाता था। हरियाणा के नारनौल के बाद इसे क्षेत्र की प्रमुख गुड़ मंडियों में गिना जाता था। हालांकि पानी की कमी के कारण समय के साथ यहां से कुछ लोगों का पलायन हुआ और आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा, लेकिन सामाजिक संबंधों में कोई खास बदलाव नहीं आया।

पीढ़ियों से कायम है आपसी भरोसा

गांव के बुजुर्ग भीमा राम बताते हैं कि यहां का माहौल हमेशा से सौहार्द पूर्ण रहा है। उनके अनुसार बचपन से ही उन्होंने सभी समुदायों को साथ रहते देखा है और आपसी सहयोग गांव की पहचान रहा है। वे एक पुरानी घटना याद करते हुए बताते हैं कि पहले गांव के एक मुस्लिम व्यापारी रात में देर हो जाने पर अक्सर उनके घर रुक जाते थे। उनके अनुसार यह विश्वास और अपनापन लंबे समय से गांव की परंपरा का हिस्सा रहा है।

झोली फैलाकर मांगी थी, भाई बनकर दी जमीन

ईदगाह से जुड़े हाजी मोहम्मद तौफीक इस पूरे घटनाक्रम को भावुक होकर याद करते हैं। वे बताते हैं कि समुदाय की ओर से जमीन की मांग की गई थी, जिसे सैनी परिवार ने खुले दिल से स्वीकार किया। उनके अनुसार जमीन के बदले पैसे देने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन परिवार ने इसे ठुकरा दिया। ईदगाह की बाउंड्री बनवाने से लेकर निर्माण की शुरुआती प्रक्रिया तक सैनी परिवार के सदस्य सक्रिय रूप से साथ रहे। स्थानीय निवासी अब्दुल रशीद इस पहल को वर्तमान सामाजिक माहौल में एक सकारात्मक संदेश मानते हैं। उनका कहना है कि इस घटना से आसपास के गांवों में भी चर्चा हुई है और लोगों ने इसे आपसी भाईचारे की मिसाल के रूप में देखा है।

सिर्फ जमीन दान नहीं, भरोसे की कहानी

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह घटना केवल जमीन दान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्षों से बने सामाजिक विश्वास की अभिव्यक्ति है। शेखावाटी क्षेत्र की परंपरा में अलग–अलग समुदायों के बीच धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर सहयोग की परंपरा रही है।

आईएएस अधिकारी Tina Dabi का तबादला, अब पति Pradeep Gawande से 426 किमी दूर नई पोस्टिंग

रानू पाठक
राजस्थान ब्यूरो प्रमुख

राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई प्रशासनिक पहल या सोशल मीडिया गतिविधि नहीं, बल्कि उनका हालिया तबादला है, जिसके बाद उनकी और उनके पति प्रदीप गवांडे के बीच भौगोलिक दूरी काफी बढ़ गई है। राज्य सरकार की देर रात जारी तबादला सूची के अनुसार टीना डाबी को बाड़मेर से हटाकर अब टोंक का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं उनके पति प्रदीप गवांडे फिलहाल जालोर के जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। नई पोस्टिंग के बाद दोनों अधिकारियों के कार्यस्थलों के बीच दूरी लगभग 186 किलोमीटर से बढ़कर 426 किलोमीटर हो गई है। टीना डाबी अब तक सीमावर्ती जिले बाड़मेर की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उनके कार्यकाल में 'नवो बाड़मेर' जैसे अभियानों और विकास कार्यों को लेकर उनकी सक्रियता चर्चा में रही। नई तबादला सूची के तहत उन्हें अब टोंक जिले की कमान सौंपी गई है। टोंक राजधानी जयपुर के नजदीक स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है, जहां प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों का स्वरूप बाड़मेर से अलग माना जाता है। ऐसे में यह पोस्टिंग उनके लिए एक नई प्रशासनिक परीक्षा के रूप में देखी जा रही है। टीना डाबी और प्रदीप गवांडे दोनों ही राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। पहले बाड़मेर और जालोर के बीच दूरी अपेक्षाकृत कम थी, जिससे दोनों के लिए पारिवारिक समन्वय आसान था। लेकिन टोंक में नई पोस्टिंग के बाद यह दूरी 426 किलोमीटर हो गई है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे उनकी निजी जिंदगी के संदर्भ में "लॉन्ग डिस्टेंस मैनेजमेंट" की नई चुनौती के तौर पर भी देख रहे हैं।

राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल

राजस्थान सरकार ने हाल ही में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए हैं। देर रात जारी आदेशों में राज्य के 65 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलाव हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मुख्यमंत्री का नया सचिव नियुक्त किया गया है।

कौन हैं टीना डाबी?

टीना डाबी देश की सबसे चर्चित युवा आईएएस अधिकारियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने 2015 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक–1 हासिल की थी। उस समय उनकी उम्र केवल 22 वर्ष थी, और वे इस परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली पहली दलित महिला उम्मीदवार बनी थीं।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

टीना डाबी का जन्म 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता जसवंत डाबी बीएसएनएल में महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए, जबकि उनकी माता हिमानी डाबी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया।

यूपीएससी में ऐतिहासिक सफलता

2015 की सिविल सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में शीर्ष स्थान हासिल करना

उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। राजस्थान कैडर में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए टीना डाबी ने विशेष रूप से बाड़मेर जिले में जल संरक्षण, प्रशासनिक सुधार और जनसंपर्क आधारित अभियानों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी कार्यशैली को सक्रिय, अनुशासित और परिणामोन्मुखी माना जाता है, जिसकी वजह से वे लगातार चर्चा में रहती हैं। टीना डाबी ने 2018 में आईएएस अधिकारी अतहर आमिर खान से विवाह किया था, जो बाद में 2021 में आपसी सहमति से समाप्त हो गया। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे से विवाह किया। दोनों अधिकारी फिलहाल अलग–अलग जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

उपलब्धियां एक नजर में

–यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 में ऑल इंडिया रैंक–1

–प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित

–राजस्थान कैडर में विभिन्न जिलों में प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व

–जल संरक्षण और स्थानीय विकास अभियानों में सक्रिय भूमिका

नई पोस्टिंग के साथ अब टोंक जिले में उनकी प्रशासनिक शैली और कार्य प्राथमिकताओं पर भी लोगों की नजर रहेगी।

54 साल बाद फिर चांद की राह Artemis II ने रचा इतिहास

करीब 54 साल बाद इंसान एक बार फिर चांद की ओर लौटने की ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़ा है। NASA का महत्वाकांक्षी Artemis&II मिशन 2 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 3:54 बजे (भारतीय समयानुसार) Kennedy Space Center से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह मिशन सिर्फ एक अंतरिक्ष उड़ान नहीं, बल्कि ''मानव सभ्यता के अगले अंतरिक्ष युग की शुरुआत'' माना जा रहा है एक ऐसा कदम, जो भविष्य में चांद पर स्थायी मौजूदगी की राह खोल सकता है।

इस ऐतिहासिक मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं

–रीड वाइसमैन (मिशन कमांडर)

–विक्टर ग्लोवर (पायलट)

–क्रिस्टीना कोच (मिशन विषेशज्ञ)

–जेरेमी हैनसेन (मिशन विषेशज्ञ)

ये सभी अंतरिक्ष यात्री व्तपवद अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद की परिक्रमा करेंगे और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आएंगे। साल 1972 में Apollo 17 मिशन के बाद पहली बार इंसान फिर से चांद के पास पहुंचने जा रहा है। हालांकि Artemis&II मिशन चांद पर उतरने वाला मिशन नहीं है, लेकिन यह आने वाले मानव मिशनों खासकर चांद पर लैंडिंग और वहां लंबे समय तक रहने की योजना के लिए बेहद अहम तैयारी है। इस मिशन से वैज्ञानिकों को मानव अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी तकनीक, सुरक्षा और गहरे अंतरिक्ष में रहने की क्षमता का परीक्षण करने का मौका मिलेगा।

54 साल बाद फिर क्यों लौट रहा है इंसान चांद की ओर? अपोलो कार्यक्रम खत्म होने के बाद अमेरिका ने दशकों तक चांद मिशनों पर ध्यान कम कर दिया था। उस समय राजनीतिक प्राथमिकताओं और बजट सीमाओं के कारण अंतरिक्ष अनुसंधान का फोकस पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पर चला गया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वैज्ञानिकों को चांद पर पानी (विशेषकर दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के रूप में) दुर्लभ खनिज और भविष्य के ईंधन संसाधनों के संकेत मिले हैं। ये संसाधन आने वाले समय की स्पेस इकोनॉमी और मंगल जैसे दूरस्थ मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसी रणनीतिक और वैज्ञानिक महत्व को ध्यान में रखते हुए Artemis कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है चांद पर इंसानों की स्थायी वापसी और आगे मंगल तक मानव यात्रा की तैयारी।

गुरमीत राम रहीम को पत्रकार हत्या मामले में बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा रद्द कर किया बरी

संजय सिन्हा
हरियाणा ब्यूरो प्रमुख

करीब दो दशक पुराने चर्चित ''पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड'' में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है।Punjab and Haryana High Court ने साल 2002 के इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है। समाचार एजेंसी ''पीटीआई'' के अनुसार, यह जानकारी राम रहीम के वकील ''जितेंद्र खुराना'' ने दी। यह फैसला उस सजा के करीब सात साल बाद आया है, जिसमें पंचकूला की विशेष अदालत ने राम रहीम को ''आजीवन कारावास'' की सजा सुनाई थी।

क्या कहा राम रहीम के वकील ने

राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा "माननीय उच्च न्यायालय की पीठ ने आज रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया है। शुरू से हमारा यही कहना था कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में ''अन्य तीन दोषियों की सजा बरकरार रखी गई है''।

पीड़ित पक्ष ने जताई निराशा, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ''अंशुल छत्रपति'' ने फैसले को निराशाजनक बताया और कहा कि वे इसे चुनौती देंगे। उन्होंने कहा "हम पिछले 24 वर्षों से इस मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले से निराशा जरूर हुई है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इस फैसले को Supreme Court में चुनौती दी जाएगी। अंशुल छत्रपति ने यह भी कहा कि अभी तक फैसले की पूरी कॉपी नहीं मिली है, इसलिए अदालत ने किन आधारों पर फैसला पलटा यह आदेश पढ़ने के बाद ही स्पष्ट होगा। मामले से शुरुआत से जुड़े वकील ''लेखराज ध ाोत'' ने कहा कि CBI की लंबी जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर ही निचली अदालत ने राम रहीम को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा "यह ध्यान देने वाली बात है कि हाईकोर्ट ने इस केस में शूटर्स और साजिशकर्ता कृष्ण लाल की सजा बरकरार रखी है। इसका मतलब है कि जांच में पर्याप्त सबूत मौजूद थे। ऐसे में डेरा प्रमुख का बरी होना पीड़ित पक्ष के लिए निराशाजनक है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि सीबीआई इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। "मर्डर केस में एक भी दिन सजा नहीं काटी" पीड़ित पक्ष के वकील ''आर.एस. बैंस'' ने कहा कि राम रहीम फिलहाल केवल ''साध्वी यौन शोषण मामलों'' में दी गई सजा काट रहे हैं। उन्होंने कहा
"रणजीत सिंह और रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में अभी तक उन्होंने सजा का एक भी दिन नहीं काटा है। रेप केस में उन्हें कुल 20 साल की सजा हुई थी, जिसमें से लगभग 8 साल पूरे हो चुके हैं।"

क्या है रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड?

यह मामला हरियाणा के सिरसा से प्रकाशित अखबार '''पूरा सच''' के संपादक रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा है। 19 अक्टूबर 2002 को हरियाणा के सिरसा में घर के बाहर बुलाकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को गोली मार दी गई। 21 अक्टूबर 2002 को अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 25 अक्टूबर 2002 को सिरसा बंद रहा और मीडिया संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया।
जनवरी 2003 में अंशुल छत्रपति ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की। दिसंबर 2003 में सीबीआई ने रामचंद्र छत्रपति और रणजीत सिंह हत्या मामलों की जांच शुरू की। नवंबर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने डेरा की याचिका खारिज कर सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश दिया। 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम दोषी करार दिए गए। 28 अगस्त 2017 को इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। 17 जनवरी 2019 को पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत ने रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई अब, करीब 24 साल बाद, हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर इस बहुचर्चित मामले को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। आगे की कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में होने की संभावना है।

कानपुर किडनी रैकेट का बड़ा खुलासा
दिल्ली-मुंबई-लखनऊ से बुलाए जाते थे डॉक्टर

कानपुर के कल्याणपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने का मामला सामने आया है। एक अस्पताल में उत्तराखंड के युवक से करीब दस लाख रुपये में किडनी खरीदने का सौदा हुआ। किडनी निकलवाने के बाद दलाल ने उसे जरूरतमंद मरीज को 90 लाख रुपये से अधिक में बेच दिया। अवैध तरीके से की गई किडनी की इस खरीद–फरोख्त का सुराग लगने पर सोमवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अस्पतालों में छापा मारा। पुलिस ने दलाल, अस्पताल संचालक, डॉक्टर दंपती समेत दस लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर के किडनी रैकेट के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमें इसकी जड़ें तक खंगालने में जुट गई हैं। टीम ने आरोपी शिवम को हिरासत में लेकर सोमवार को कई घंटों तक पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया है कि कैसे किडनी खरीद का काला धंधा चलता है।

आरोपी ने बताया कि शक न हो इसके लिए किडनी खरीदने वाले को अपना रिश्तेदार बताया जाता है। उसे गरीब और परिवार का एकमात्र सहारा बताकर कम से कम दाम में सौदा करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जरूरतमंद के परिजन को उसकी गिरती सेहत का हवाला देकर जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम करने के लिए कहा जाता है। बाद में उसे एक डोनर के विषय में बताकर उसकी खर्च करने की हैसियत आकी जाती है। जरूरतमंद के परिजन के तैयार होने पर उसे कई गुना मुनाफा लेकर बेचा दिया जाता है।

कानपुर में अभी कई ऐसे अस्पताल

ऐसे में अब पुलिस उन अस्पतालों के बारे में जानकारी जुटा रही है जिनमें ट्रांसप्लांट किया गया, या इसके बाद मरीज और डोनर को भर्ती कर उनका उपचार किया गया। पुलिस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि सभी अस्पताल बर्रा, नौबस्ता, पनकी और कल्याणपुर जैसे क्षेत्रों में चल रहे हैं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इन अस्पतालों में मरीज को गाल ब्लैडर, पथरी या आंतों का रोगी बताकर भर्ती किया जाता था। जहां डोनर को जल्द छुट्टी दे दी जाती। किडनी लेने वाले मरीज को कई माह तक भर्ती रखा जाता। हर अस्पताल में उसके बारे में नई बीमारी बताई जाती है। आरोपी की जानकारी से पता चला है कि रैकेट में ट्रांसप्लांट मामले से जुड़े रहे कई डॉक्टर और नर्सिंग होम के नाम शामिल हैं। पुलिस की टीमें उसके बताए गए अस्पतालों और डॉक्टरों से पूछताछ कर सच्चाई जानने में जुट गई हैं। चर्चा है कि पुलिस की टीमें पश्चिम बंगाल और हरियाणा भी गई हैं।बताया जा रहा है कि वहां के युवकों से भी किडनी की खरीद फरोख्त हुई है। मामले में पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि किडनी ट्रांसप्लाट के मामले में जितने भी नाम सामने आए हैं, सभी की भूमिका की जांच की जा रही है।

22 साल पहले भी सामने आया था किडनी खरीद का मामला

22 साल पहले भी शहर में किडनी की खरीद–फरोख्त का मामला सामने आया था। इसमें पॉश इलाके में स्थित एक नर्सिंग होम और उसमें कार्यरत सर्जन का नाम प्रकाश में आया था। आरोप था कि रैकेट में शामिल आर्थिक रूप

से कमजोर या किसी अन्य बीमारी का इलाज कराने आए मरीज की उसके संबंधित जांचों के साथ की किडनी की भी जांच की जाती थी। जिस मरीज को किडनी की जरूरत होती थी, उससे मैच करने पर किडनी निकालकर ट्रांसप्लांट की जाती थी। मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में सीबीसीआईडी ने इस मामले की जांच की थी। इसमें शामिल सर्जन वर्तमान में भी चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पुलिस को आवास विकास स्थित आरोही हॉस्पिटल में किडनी डोनर भर्ती मिला है। यह हॉस्पिटल करीब दो माह पहले बंद हो चुका है। सूत्रों के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मरीज को हॉस्पिटल के संचालक राजेश के कहने पर भर्ती कराया गया था। पुलिस को मौके से मरीज के नाम का हॉस्पिटल वाला पर्चा मिला है। किडनी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने किडनी डोनेट करने वाले और ट्रांसप्लांट कराने वाले की सेहत को देखते हुए उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। देर शाम को एंबुलेंस से पुलिस सुरक्षा में दोनों को अस्पताल भेजा गया था।

दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से आते थे डॉक्टर

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लखनऊ, मुंबई और दिल्ली से स्पेशलिस्ट बुलाए जाते थे। ट्रांसप्लांट की टीम में नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट सर्जन, यूरोलॉजी और ग्राफ्टिंग एक्सपर्ट होते थे। साथ ही एनेस्थेसिस्ट, डायटीशियन भी टीम का हिस्सा होते थे।

दलाल और डॉक्टर दंपती समेत दस हिरासत में

कानपुर के कल्याणपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने का मामला प्रकाश में आया है। यहां के एक अस्पताल में उत्तराखंड के युवक से करीब दस लाख रुपये में किडनी खरीदने का सौदा हुआ। किडनी निकलवाने के बाद दलाल ने उसे जरूरतमंद मरीज को 90 लाख रुपये से अधिक में बेच दिया।

अवैध तरीके से की गई किडनी की इस खरीद–फरोख्त का सुराग लगने पर सोमवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अस्पतालों में छापा मारा। पुलिस ने दलाल, अस्पताल संचालक, डॉक्टर दंपती समेत दस लोगों को हिरासत में लिया है। एक अस्पताल का संबंध आईएमए के एक बड़े पदाधिकारी से बताया जा रहा है। कल्याणपुर के आवास विकास तीन निवासी शिवम अग्रवाल पर आरोप है कि उसने उत्तराखंड के युवक को दस लाख में किडनी बेचने का ऑफर दिया था।बताया था कि उसके रिश्तेदार को किडनी की जरूरत है। रुपयों की जरूरत के चलते युवक ने हामी भर दी। रावतपुर स्थित एक अस्पताल में किडनी निकाली गई। दलाल शिवम ने इसी अस्पताल में भर्ती मुजफ्फरनगर की महिला मरीज (35) के परिजन को 90 लाख रुपये से अधिक में किडनी बेच दी। सूत्रों के मुताबिक किडनी बेचने वाले युवक को छह लाख रुपये नकद और 3.5 लाख का चेक दिया। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद दोनों मरीजों को 24 घंटे तक इसी अस्पताल में रखा गया इसके बाद दोनों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि कुछ मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। किडनी रैकेट की जांच कर रही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार रात तीन अस्पतालों में छापा मारा। इनमें कल्याणपुर आवास विकास एक नंबर स्थित प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, केशवपुरम रोड स्थित आहूजा हॉस्पिटल, पनकी कल्याणपुर रोड स्थित मेडलाइफ हॉस्पिटल शामिल हैं। टीम ने किडनी संबंधी रोगों के भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी जुटाई। छापे की इस कार्रवाई को किडनी रैकेट से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इसमें से कुछ अस्पताल किडनी के अवैध ट्रांसप्लांट मामले में शामिल हो सकते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी खुलकर आरोपियों की गिरफ्तारी या भूमिका के बारे में बोलने से बच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दस लाख में सौदा तय होने के बाद डोनर को सिर्फ 9.5 लाख रुपये दलाल शिवम ने दिए थे। 50 हजार के लिए शिवम उसे टरका रहा था। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। पुलिस ने जांच की तो किडनी रैकेट की परतें खुलती चली गईं। देर रात क्राइम ब्रांच ने युवक के बताए दोनों अस्पतालों में छापा मारा। जांच में वहां उसके भर्ती होने के सबूत मिले हैं।

क्राइम ब्रांच ने दोनों हॉस्पिटल के संचालक, डॉक्टर दंपती और दलाल शिवम को हिरासत में लिया। वहीं, किडनी लेने वाली मरीज को भी आवास विकास के एक अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया था। पुलिस ने उस हॉस्पिटल में भी जांच की। वहां से पांच अन्य लोगों को उठाकर पूछताछ की जा रही है।

कर्टसी–अमर उजाला

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विशेष

विभाजन के दर्द से लेकर फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ बनने तक डॉ. गोपी चंद खिलनानी का सफर

विश्व स्तर पर सम्मानित फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व विशेषज्ञ डॉ. गोपी चंद खिलनानी ने भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सरकारों को सलाह दी है और तीन उप–राष्ट्रपतियों, कैबिनेट मंत्रियों और विदेशों में रहने वाले विशेष अतिथियों सहित देश के सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारियों की देखभाल की है। फिर भी उनका जीवन सम्मेलन कक्षों और नीतिगत कमरों से बहुत दूर शुरू हुआ। जब गोपी चंद खिलनानी का जन्म 1954 में हुआ, तब विभाजन के घाव लाखों विस्थापित परिवारों के बीच अभी भी ताजा थे। महज सात साल पहले, उनके माता–पिता, जो दोनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे, को पाकिस्तान के सिंध में स्थित अपना पैतृक घर छोड़ने और भारत में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय के अनगिनत शरणार्थियों की तरह, उन्होंने भी अपना जीवन नए सिरे से संवारा और अंततः जयपुर में शरण पाई। जयपुर की चारदीवारी के भीतर एक पुनर्वास बस्ती में पले–बढ़े, पाँच भाई–बहनों में सबसे छोटे, युवा गोपी ने 1947 की भयावह घटनाओं से बचे परिवारों के दर्द, हानि और दृढ़ता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। विस्थापन और बलिदान की कहानियों से भरे उन शुरुआती वर्षों ने उन पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे उनमें सहानुभूति, दृढ़ता और एक मजबूत नैतिक दिशा का संचार हुआ, जिसने उनके जीवन का मार्गदर्शन किया। खिलनानी परिवार के लिए शिक्षा और मूल्य सर्वोपरि थे। सीमित साधनों के बावजूद, उनके माता–पिता ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा सर्वोपरि रहे। गोपी सहित पाँच भाई–बहनों में से चार विश्व स्तर पर ख्यातिप्राप्त डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने की प्रेरणा मुझे मेरी बड़ी बहन से मिली, जो स्वर्ण पदक विजेता थीं और हमारे परिवार में चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति थीं, पीएसआरआई इंस्टिट्यूट ऑफ पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के अध्यक्ष डॉ. गोपी चंद खिलनानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक ऐसे स्कूल में पढ़ने से लेकर, जहाँ कक्षाएँ कभी–कभी पेड़ के नीचे या अस्थायी झोपड़ी में लगती थीं, जयपुर के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज से स्नातक होने और बाद में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित माउंट सिनाई मेडिकल स्कूल में क्रिटिकल केयर में फेलोशिप पूरी करने तक, डॉ. खिलनानी का सफर इस बात का एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे दृढ़ संकल्प परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है। सहानुभूति पर आधारित सेवा "बचपन से ही, मैं अपने पड़ोस के दो डॉक्टरों का बहुत बड़ा प्रशंसक था," वे याद करते हैं। "उन्हें भगवान की तरह माना जाता था। हर कोई उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए उनका सम्मान करता था।" यह श्रद्धा उनके मन में बनी रही, जिसने चुपचाप उनके पेशे को आकार दिया। 41 वर्षों से अधिक के नैदानिक अनुभव के साथ, डॉ. खिलनानी ने कई विशिष्ट भूमिकाएँ निभाई हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर विभाग के प्रमुख और प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है, और पिछले दो दशकों में भारत के तीन उपराष्ट्रपतियों के चिकित्सक रहे हैं। उनके मरीजों की सूची में वरिष्ठ अधिकारी, कैबिनेट मंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य शामिल हैं। उन्हें विदेशों में रहने वाले विशेष अतिथियों को विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह प्रदान करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। चाहे अमीर हो या शक्तिशाली, या गरीब और कमजोर, मैं सभी के साथ एक ही उत्साह और लगन से पेश आता हूँ," वे कहते हैं। "गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों की देखभाल करना हमेशा से मेरा जुनून रहा है।" चिकित्सा में विश्वास और करुणा के प्रबल समर्थक डॉ. खिलनानी का मानना है कि एक स्वस्थ डॉक्टर–मरीज संबंध नैदानिक उत्कृष्टता जितना ही महत्वपूर्ण है। उनकी देखभाल का दर्शन सहानुभूति पर आधारित है, जिसमें कोई भेदभाव या ऊँच–नीच नहीं है। भारत की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को विश्व के सामने रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ समिति के सदस्य डॉ. खिलनानी ने अस्थमा, सीओपीडी (ब्रोंकाइटिस), निमोनिया और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों पर कई अभ्यास दिशा निर्देश लिखे हैं। उनके शोध कार्य के कारण उन्हें जिनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह तैयार करने में योगदान दिया। जैसे–जैसे वायु प्रदूषण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में उभरा, विशेष रूप से नई दिल्ली जैसे शहरों में, डॉ. खिलनानी राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक जाना–पहचाना चेहरा बन गए, जो नियमित रूप से नागरिकों को निवारक उपायों और स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में सलाह देते थे। "वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पूरे भारत के लिए एक गंभीर मुद्दा है," वे कहते हैं। ष्हालांकि नीतिगत हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं, फिर भी व्यक्ति नुकसान को कम करने के लिए निवारक कदम उठा सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार की उस समिति में भी अपनी सेवाएं दीं जिसने वायु गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया, जिसका उपयोग अब पूरे देश में प्रदूषण स्तर का आकलन और संचार करने के लिए प्रतिदिन किया जाता है। कोविड–19 के दौरान अग्रिम पंक्ति में जब कोविड–19 महामारी फैली, तो डॉ. खिलनानी शुरुआत से ही इसमें शामिल थे। उन्होंने दिल्ली सरकार की विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया, जिसे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आने वाले संकट के लिए तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। वे कहते हैं, "महामारी के दौरान, मैंने लगातार चिकित्सा जगत और जनता को सलाह दी, परामर्श जारी किए, वेबिनार में भाग लिया और राष्ट्रीय टेलीविजन के माध्यम से अपडेट साझा किए।" उन्होंने कोवैक्सिन परीक्षण के लिए निर्णायक समिति में भी कार्य किया, जिससे इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत की वैक्सीन मूल्यांकन प्रक्रिया में योगदान दिया। साधारण शुरुआत और विशिष्टता से भरा जीवन डॉ. खिलनानी की यात्रा मोती डूंगरी के बाल मंदिर से शुरू हुई, जहाँ मासिक स्कूल शुल्क मात्र एक रुपया था। वे याद करते हैं, "स्कूल ने हमें जीवन के लिए तैयार करने के लिए बागवानी और बढ़ईगीरी जैसे व्यावहारिक कौशल पर विशेष जोर दिया।" बाद में उन्होंने हिंदी माध्यम के विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने उत्कृष्ट अंकों

के साथ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता के कारण उन्हें राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति मिली, जिसने सात वर्षों तक, उनकी मेडिकल स्नातक की पढ़ाई पूरी करने में उनका सहयोग किया। डॉ. खिलनानी कहते हैं, "मेरे पिता ने अपना जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया और एक संत समान जीवन व्यतीत किया। उनके आदर्श मुझे उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।" एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी छात्र, उन्होंने बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना भी कई पुरस्कार जीते। उन्हें गायन का भी शौक था और वे बचपन से ही नियमित रूप से मंच पर प्रस्तुति देते थे। बढ़ते खतरे को भांपते हुए, उन्होंने आईसीयू आधारित संक्रमण संबंधी कई अध्ययनों का नेतृत्व किया और 2019 में इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के तहत आईसीयू में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए। साक्ष्य–आधारित इन दिशानिर्देशों को 2024 में संशोधित और अद्यतन किया गया और अब इनका पूरे भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नॉन–इनवेसिव वेंटिलेशन के नैदानिक अनुप्रयोग में अग्रणी डॉ. खिलनानी ने चिकित्सकों को इस जीवन रक्षक हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से अपनाने में मदद करने के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश भी विकसित किए। फेलोशिप, मान्यता और अध्यापन को अपना पेशा बनाना वर्षों से, डॉ. खिलनानी को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, इंडियन चेस्ट सोसाइटी, इंडियन स्लीप डिसऑर्डर्स एसोसिएशन और नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस सहित कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के फेलो के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने 2007 से 2009 तक नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के उपाध्यक्ष के रूप में और बाद में दो कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पिछले वर्ष, उन्होंने काठमांडू में एक विशिष्ट भाषण दिया और उन्हें नेपाली रेस्पिरेटरी सोसाइटी की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई। उपाधियों और सम्मानों से परे, शिक्षण ही उनका सबसे बड़ा जुनून है। "डॉक्टरों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना मुझे अपार संतुष्टि देता है, " डॉ. खिलनानी कहते हैं, जिन्होंने पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन में एमबीबीएस, एमडी और डीएम के छात्रों की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है। एक सख्त अनुशासनवादी के रूप में जाने जाने के बावजूद, उनके छात्र उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनका सम्मान न केवल उनकी कठोरता के लिए है, बल्कि उस ईमानदारी और उत्कृष्टता के लिए भी है जो वे पेशे में लाते हैं।

-Courtesy-
theglobalindian.com

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 : बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है विज्ञान - डॉ. जुगल किशोर

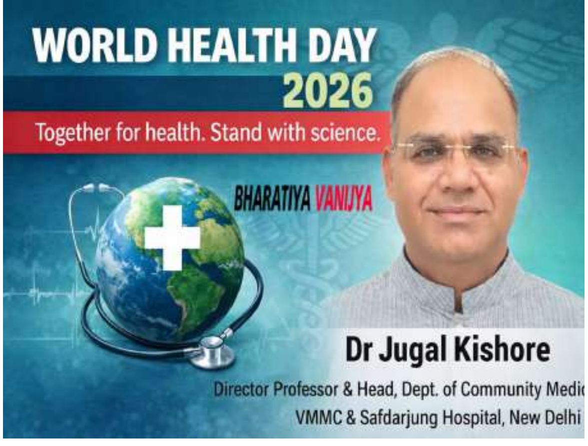

विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे 1950 से मनाया जा रहा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की याद दिलाता हैय इस संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इस दिन का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं हैय इसका लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जाने–माने जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. जुगल किशोर के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य दिवस महज एक तारीख से कहीं बढ़कर हैकृयह अपने और समाज के स्वास्थ्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का एक अवसर है। हर साल, WHO एक नई थीम पेश करता है जो किसी विशेष वैश्विक स्वास्थ्य चिंता पर केंद्रित होती है। इस साल की थीम, स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े हों (Together for Health] Stand with Science), आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। डॉ. किशोर बताते हैं कि विज्ञान के साथ खड़े हों का अर्थ है कि स्वास्थ्य से जुड़े सभी निर्णय वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होने चाहिए। आज के डिजिटल युग में, गलत जानकारी, मिथक और बिना पुष्टि वाले दावे अक्सर लोगों के चुनाव को प्रभावित करते हैं, जो हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकों के बीच वैज्ञानिक सोच (scientific temper) के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह इस विचार को दर्शाता है कि समाज में प्रगतिकृविशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र मेंकृतर्क, अनुसंधान और प्रमाणों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। टीकाकरण अभियान, स्वच्छता अभियान और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपनाना जैसी पहलें इसी वैज्ञानिक मानसिकता में निहित हैं। डॉ. किशोर बताते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ तेजी से बदल रही हैं। मधुमेह, हृदय रोग और मानसिक तनाव जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। इसके अलावा, महामारी और पर्यावरणीय बदलाव जैसे वैश्विक संकट जन स्वास्थ्य को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, सरकारों, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और नागरिकों के बीच सहयोग अनिवार्य हो जाता है। वह बताते हैं कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और दवाओं तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी दैनिक आदतों से गहराई से जुड़ा है, जिसमें आहार, स्वच्छता, शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकताकृये सभी एक स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। निष्कर्ष के तौर पर, डॉ. जुगल किशोर का मानना है कि शविश्व स्वास्थ्य दिवसश हमें यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। स्वास्थ्य के लिए एकजुट (Together for Health) के सिद्धांत को अपनाकर और विज्ञान के साथ मजबूती से खड़े होकर, हम एक अधिक स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं।

मां का साया छूटा, चाचा ने निभाया साथ संघर्ष से आईपीएल तक पहुंचे अनिकेत वर्मा

श्वेतांक वर्मा
मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख

आईपीएल हमेशा से सिर्फ बड़े सितारों का मंच नहीं रहा, बल्कि यह उन नए खिलाड़ियों के सपनों को भी उड़ान देता है जो अपनी मेहनत से पहचान बनाना चाहते हैं। हर सीजन कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जो अचानक चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। इस बार ऐसा ही एक नाम है कृ अनिकेत वर्मा। आईपीएल के 19वें सीजन के शुरुआती मुकाबले में जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रॉयल चौलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैदान में उतरी, तो मैच भले ही आरसीबी ने अपने नाम कर लिया, लेकिन इस मुकाबले ने कई व्यक्तिगत प्रदर्शन को सुर्खियों में ला दिया। एक ओर टपतंज ज्ञवीसप की बल्लेबाजी चर्चा में रही, वहीं हैदराबाद की ओर से Ishan Kishan की 38 गेंदों पर 80 रनों की तेज पारी ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक और नाम उभरा कृ अनिकेत वर्मा। उन्होंने सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का दमदार परिचय दिया। उनकी इस पारी में तीन चौके और चार छक्के शामिल थे। उनकी इस तेज पारी की बदौलत टीम 200 के पार पहुंच सकी और फ्रेंचाइजी ने भी उनकी सराहना करते हुए लिखा '"बेहतरीन खेल, अनिकेत वर्मा।"'लेकिन अनिकेत की यह चमक अचानक नहीं आई। इसके पीछे संघर्ष, त्याग और परिवार का साथ छिपा है।

बचपन का संघर्ष तीन साल की उम्र में मां को खोया, चाचा बने सहारा

अनिकेत वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ, लेकिन बाद में उनका परिवार मध्य प्रदेश के भोपाल में आकर बस गया। जीवन की शुरुआत ही कठिनाइयों से हुई महज तीन साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया। आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर थी। परिवार किराए के घर में रहता था और सीमित साधनों के बीच ही अनिकेत ने क्रिकेट खेलने का सपना देखा। इस कठिन दौर में उनके चाचा ने उनका साथ नहीं छोड़ा। खुद अनिकेत बताते हैं, "जब हम भोपाल आए तो आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। चाचा वहीं रहते थे, हम उनके साथ रहने लगे। संघर्ष का एक भावुक प्रसंग वे आज भी याद करते हैं। "अंडर–15 ट्रायल के लिए जाना था, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था। उस समय चाचा की नौकरी सिर्फ दो–तीन हजार रुपये की थी। फोन करीब सात हजार रुपये का था। उन्होंने लोगों से उधार लेकर मेरे लिए फोन खरीदा।" आज वही अनिकेत अपने परिवार के लिए घर खरीद चुके हैं कृ यह सफर उनकी मेहनत का प्रमाण है। आईपीएल 2025 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने अनिकेत वर्मा को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया। खास बात यह रही कि उस समय तक उन्होंने टीम इंडिया के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने उनके टैलेंट पर भरोसा दिखाया और अनिकेत ने मौके को सही साबित करने की शुरुआत कर दी है। अनिकेत वर्मा को घरेलू क्रिकेट में मिडिल–ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2024 में अंडर–23 वनडे टूर्नामेंट में कर्नाटक के खिलाफ मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए उन्होंने 75 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए। इस पारी में छह चौके और आठ छक्के शामिल थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सात मैचों में 184 रन बनाए, जिसमें 16 छक्के शामिल रहे। इस दौरान उनका औसत 46 और स्ट्राइक रेट 152.06 रहा। इससे पहले जून 2024 में मध्य प्रदेश लीग में भोपाल लेपर्ड्स के लिए खेलते हुए उन्होंने छह पारियों में 273 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 195.00 रहा कृ जो उनके आक्रामक खेल की पहचान बन गया। इसी लीग में उन्होंने 41 गेंदों पर 123 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 13 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत टीम ने 278 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से आईपीएल तक

सीनियर स्तर पर अनिकेत ने अपना पहला टी20 मैच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की ओर से हैदराबाद के खिलाफ खेला। हालांकि उस मुकाबले में वे बिना खाता खोले आउट हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पदार्पण करने से पहले उनके नाम सिर्फ यही एक सीनियर टी20 मैच दर्ज था। लेकिन मौके ने उन्हें नहीं रोका कृ बल्कि उन्होंने उसी मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपने दूसरे मैच में अनिकेत ने 13 गेंदों पर 36 रन बनाए, जिसमें पांच छक्के शामिल थे। इसके बाद अगले मैच में उन्होंने 41 गेंदों पर छह छक्कों की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। पिछले सीजन में उन्होंने टीम के लिए सभी 14 मैच खेले और 166.19 के स्ट्राइक रेट से 236 रन बनाए। आईपीएल के इस नए सीजन में जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ अनिकेत वर्मा ने शुरुआत की है, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले मैचों में क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब उन पर टिकी रहेंगी। संघर्ष से निकली यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि उस विश्वास की मिसाल है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपनों को सच कर सकता है।

उत्तराखंड के दिव्यांग कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया

सुनील नेगी
उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख

पिछले 5 अप्रैल को दिल्ली के मावलंकर हॉल में असाधारण प्रतिभाओं से परिपूर्ण दिव्यांग कलाकारों की एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और सभी ने इसका भरपूर आनंद उठाया। इनमें से अधिकांश दिव्यांग कलाकार उत्तराखंड के भीतरी गांवों से आए थे। प्रख्यात संगीतकार राजेंद्र चौहान, जिन्हें उत्तराखंड का स्वर कोकिला कहा जाता है, उनकी पत्नी कल्पना चौहान और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षिका एवं प्रसिद्ध कलाकार राखी बिष्ट ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रतिष्ठित मंच प्रदान किया, जहां बीस उत्कृष्ट कलाकारों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें सशक्तिकरण और अपनेपन की भावना भी प्रदान की गई। पार्वतीया सांस्कृतिक संस्था और रविशा फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित और छह अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा प्रायोजित उत्तराखंड विशेष रूप से सक्षम महोत्सव नामक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कलाकारों ने दर्शकों से जबरदस्त उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त की, जिन्होंने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। कुल बीस कलाकारों, जिनमें विशेष रूप से विकलांग संगीतकार भी शामिल थे, को उत्तराखंड की दिग्गज गायिका कल्पना चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित कलाकारों के नाम हैंरू निर्मला देवी, रेखा मेहता, प्रेमा विश्वास, सुरेंद्र लाल, विजय बिष्ट, प्रवीण नेगी, नीरज सिंह रावत, रजत कुमार पंचाल, नीलिमा रॉय, सुनील कुमार, निर्मल कुमार, अंजली, मुकेश कुमार, धन सिंह, मानस पांडे, कल्पना चौहान, महेशानंद, रोशन लाल और पूरन सिंह। पूरे कार्यक्रम का संचालन राखी बिष्ट और राजेंद्र चौहान ने कुशलतापूर्वक किया, जिन्होंने निर्देशक के रूप में संगीत संध्या का संचालन भी किया।मावलंकर हॉल खचाखच भरा हुआ था।दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कुलदीप वत्स इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिनका श्री बत्रा, सुश्री राखी बिष्ट और राजेंद्र चौहान ने अभिनंदन किया। यह शाम वाकई यादगार रही।

Maharani® Rice

CHAMAN

LAL SETIA EXPORTS LTD

"First, we eat Maharani Rice,
Then we do everything else."

VEG BIRYANI

www.maharanirice.in begum@futurerice.com

एनएचपीसी का हरित ऊर्जा नेतृत्व

180 मेगावाट से 9082.9 मेगावाट तक की यात्रा

अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए 31 नवीकरणीय ऊर्जा पावर स्टेशनों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति।

सुदृढ़ वित्तीय प्रदर्शन

अपनी स्थापना के बाद से निरंतर सुदृढ़ परिणाम प्रदर्शित कर रही है।

14 सक्रिय परियोजनाएं

संधारणीय भविष्य के लिए, 9204 मेगावाट क्षमता का निर्माण कर रही है।

एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देना

वर्ष 2032 तक 23,000 मेगावाट और वर्ष 2047 तक 50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य।

भारत की दो सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण

सुबनसिरी लोअर परियोजना: 2,000 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश और असम में।
दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना: 2,880 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश में।

नवरत्न का दर्जा

कार्यनीतिक महत्व को मान्यता देते हुए 30 अगस्त, 2024 को प्रदान किया गया।

भविष्य के लिए विजन

एनएचपीसी संधारणीय ऊर्जा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन के प्रति समर्पित है।

आइए,
हम सब मिलकर हरित ऊर्जा में नेतृत्व की विरासत का उत्सव मनाएं!

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

हमसे जुड़ें :